

खण्ड-07 सत्र-05
अंक-58

सोमवार 26 फरवरी, 2024
07 फाल्गुन, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा
पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

राज कुमार
सचिव
RAJ KUMAR
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप-सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 सोमवार, 26 फरवरी, 2024/07 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-58

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-35
3.	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	36-90

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-5 सोमवार, 26 फरवरी, 2024/07 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-58

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. श्री अजेश यादव | 11. श्री हाजी युनूस |
| 2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी | 12. श्री जय भगवान |
| 3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए. | 13. श्री कुलदीप कुमार |
| 4. श्री अब्दुल रहमान | 14. श्री महेन्द्र यादव |
| 5. सुश्री भावना गौड | 15. श्री मदन लाल |
| 6. श्री बी. एस. जून | 16. श्री नरेश बाल्यान |
| 7. श्री धर्मपाल लाकड़ा | 17. श्री नरेश यादव |
| 8. श्री दिनेश मोहनिया | 18. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर |
| 9. श्री दुर्गेश पाठक | 19. श्री प्रवीण कुमार |
| 10. श्री गिरीश सोनी | 20. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस |

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 21. श्री राजेश गुप्ता | 31. श्री सही राम |
| 22. श्री राजेन्द्र पाल गौतम | 32. श्री एस. के. बग्गा |
| 23. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों | 33. श्री विनय मिश्रा |
| 24. श्री राजेश ऋषि | 34. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान |
| 25. श्री रोहित कुमार | 35. श्री अजय दत्त |
| 26. श्री शरद कुमार चौहान | 36. श्री महेंद्र गोयल |
| 27. श्री संजीव झा | 37. श्री पवन शर्मा |
| 28. श्री सोमदत्त | 38. श्री सुरेंद्र कुमार |
| 29. श्री शिवचरण गोयल | 39. श्री विशेष रवि |
| 30. श्री सोमनाथ भारती | |

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 सोमवार, 26 फरवरी, 2024/07 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-58

दिल्ली विधान सभा

सदन 11.12 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। 280 श्री जरनैल सिंह जी, (अनुपस्थित) श्री राजेश गुप्ता जी, (अनुपस्थित) श्री शिव चरण गोयल जी। शिवचरण जी परसों भी मैंने टोका था आपकी ऐलोटिड सीट कौन सी है। बोलने के लिए ऐलोटिड सीट पर ही खड़े होना पड़ेगा। प्लीज।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री शिव चरण गोयल: अध्यक्ष जी नमस्कार, धन्यवाद आपका, आज मुझे सबसे पहले सदन में बोलने का मौका मिला, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपका ध्यान मेरी मोती नगर विधानसभा और पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर जिस समस्या से गुजर रहे हैं, आज ये हर घर की समस्या है। आज यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने में हमें सोचना पड़ता है

कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें आज मेरे घर में मेरा पोता है, पोती है आज उन बच्चों को हम डर से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं भी जब रात को निकलता हूं तो हाथ में डंडा ले के निकलता हूं और ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको और पिछले एक साल छोड़ दें तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में थी और उस समय यदि ये उस तरह से कार्यवाई कर लेते, उस पर ठोस परिणाम ले के आते तो आज दिल्ली की और देश की इस तरह की भयावह स्थिति नहीं होती और आज जब भी आफिस में जाते हैं तो लोग अपनी कंप्लेंट ले के आते हैं कि कुत्ते बढ़ गए हैं, काट रहे हैं। हमारे पंजाबी बाग में पांच नंबर रोड़ पर एक कुत्ता पागल हो गया है। हम बात करते हैं अधिकारियों से वो कहते हैं जी हम तो इसकी नसबंदी कर सकते हैं sterilize कर सकते हैं और हमारे पास कोई इसका जरिया नहीं है। एक जे जे पार्क में एक ने कुत्ता पाल रखा है पिटबुल। ये कुत्ता ऐसा है कि ये काटेगा काटेगा। उसकी भी कंप्लेंट तीन महीने पहले पुलिस स्टेशन में की गई और वो कम से कम नहीं बारह लोगों को काट चुका है। तो आज ये समय समस्या बड़ी भयावह होती जा रही है और कल दिल्ली के अंदर डेढ़ साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंच डाला और वो मर गई और मैं इस तरह की वारदात अखबारों में लगातार पढ़ रहा हूं। ये कोई दिल्ली की समस्या नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हैदराबाद में एक घटना घटी जिसमें ये 2 फरवरी 2024 की बात है और ये 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपी है कि एक साल का बच्चा उसको कुत्तों ने नोंच डाला, फिर 14 जनवरी

भारतीय जनता पार्टी शासित मध्यप्रदेश, भोपाल जिसके अंदर डेढ़ साल के बच्चे को कुत्तों ने रौंद डाला।

माननीय अध्यक्ष: शिवचरण गोयल जी जो लिख के दिया है उससे बाहर जा रहे हैं आप प्लीज।

श्री शिव चरण गोयल: मैं तो थोड़ा सा इसको अटैच कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आज जो समस्याएँ हैं वो इतनी गंभीर हैं कि यदि इस पर हमने कोई ठोस डिजीजन नहीं लिये, मैं कुछ और नहीं जोड़ रहा हूँ। और दो साल का बच्चा गुजरात के अंदर उसको भी कुत्तों ने नोंच डाला। तो आज ये समस्या बकायदा पूरी दिल्ली में हमारे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी के पोस्टर लगे हुए हैं कुत्तों के बारे में और उन्होंने कहा भी था तीन साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी बिल्कुल नालायक है और अभी हमारा रिजल्ट आया है कि हमने इतना बेहतर काम किया है कि हम 40 प्वाइंट्स उपर उठ चुके हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी केंद्र की है और केंद्र जब तक इसके उपर कोई ठोस, इसके उपर कोई नियम नहीं बनायेगा, इसके उपर एक्शन नहीं लिया जायेगा तो पूरे देश की सरकारें सारी बेबस हैं। अध्यक्ष जी, आपसे एक विनती है अध्यक्ष जी आप इसके उपर कोई लैटर लिखकर केंद्र सरकार को सचेत करेंगे कि इसके उपर कोई ऐसा कानून बनाया जाये जिसके उपर पूरे निवासियों को, सभी को राहत मिल सके। मुझे आपने इस गंभीर और भयावह मुद्दे पर बोलने का मौका दिया बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री जय भगवान जी

श्री जय भगवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 280 के तहत मुझे अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कुछ डीडीए के रोड जो बड़े बड़े रोड हैं लेकिन बंद हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे बवाना विधान सभा के अंदर एलजी साहब ने कुतुबगढ़ गांव गोद ले रखा है और वो डीडीए के चेयरमैन भी हैं और बार बार उन रोडों से होकर के गुजरते हैं लेकिन उनका ध्यान उन रोडों पे नहीं जाता। तो मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से एलजी साहब का ध्यान इन रोडों पर लेकर जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक 80 मी. रोड है मेरा यूईआर-3 । अध्यक्ष महोदय, ये पंसाली में पिछले 30 साल से बंद है और लोग इसपर करीब साईड से एक रोड है 20 फुट का उससे होकर के गुजरते हैं जबकि ये करीब करीब 80 मीटर 270 फुट का आसपास रोड है। इसे खोल देना चाहिये बस एक 100 मीटर का टुकड़ा है अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से ये रोड रूका हुआ है। लेकिन एलजी साहब का ध्यान इसपे नहीं जा रहा अध्यक्ष महोदय और लोग जाम में लगातार फंसे रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा रोड है 45 मीटर रोड जो सेक्टर 26 से सेक्टर 27 को जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये मास्टर प्लान रोड है और इस मास्टर प्लान रोड से कई सेक्टरों का आने जाने का ये मेन रोड है और इससे सेक्टर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 सेक्टर और मेरे जो पूरे गांव हैं बवाना के उनको बिल्कुल नान स्टाप जो जाम में फंसे रहते हैं लोग, बिल्कुल जाम में नहीं फंसेंगे लेकिन एलजी साहब बार बार कुतब गढ़

जा रहे हैं लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं है। ये करीब करीब 600 मीटर का टुकड़ा है अगर ये खोल दिया जाए अध्यक्ष महोदय तो लोग को जाम से मुक्ति मिलेगी, लाखों लोगों को फायदा होगा इससे। अध्यक्ष महोदय तीसरा मेरा रोड़ है 45 मीटर रोड़ ये भी मास्टर प्लान रोड़ है अध्यक्ष महोदय और ये सैक्टर 23 और 24 के बीच से गुजरता है जो कि सैक्टर 24 से जहां पर अभी स्पोर्ट काम्पलैक्स बन रहा है वहां पर भी एलजी साहब अभी जल्दी उदघाटन करने वाले हैं और सीधा वहां से लेकर के और सीधा विश्राम चौक तक अध्यक्ष महोदय ये एक किलोमीटर का फेज है अगर ये खुल जाए तो मैं कह रहा हूं इससे भी लाखों लोगों को फायदा होगा अध्यक्ष महोदय।

चौथा मेरा रोड़ है अध्यक्ष महोदय 45 मीटर रोड़ है सैक्टर 27 से डीटीयूजो कि प्लानिंग में है अध्यक्ष महोदय ये रिंग रोड़ पर जाएगा तो जो हमारे बवाना इंडस्ट्रीयल एरिया के जो फैक्ट्री के जो लोग हैं या वैसे जो गांव के जो लोग हैं उनको इसका सीधा फायदा होगा अध्यक्ष महोदय तो ये भी खुलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय पांचवा मेरा रोड़ है सैक्टर बीस सुल्तानपुरी चौक से लेकर सैक्टर 22 तक जो यूईआर को निकलता है अध्यक्ष महोदय तो यहां पर जो एंट्री पर करीब सौ मीटर का टुकड़ा है जो कि एक तरफ से बना हुआ है एक तरफ से नहीं बना हुआ है और आगे जाकर के करीब करीब तीन सौ चार सौ मीटर रोड़ पूरी तरीके से टूटा हुआ है अगर ये बन जाए तो लाखों लोगों को इससे फायदा होगा किराड़ी को भी इससे फायदा होगा अध्यक्ष महोदय। एलजी साहब अभी किराड़ी भी गए थे अध्यक्ष महोदय बिल्कुल उसके

बिल्कुल नजदीक से होकर गए थे उसी रोड़ के साइड से लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी उस पर नहीं गया। अध्यक्ष महोदय मेरा छठा रोड़ है साठ मीटर रोड़ जो बवाना रोड़ से जैन कालोनी को निकलता है अध्यक्ष महोदय ये भी करीब सौ से डेढ़ सौ मीटर का टुकड़ा है जो बिल्कुल बंद है। अगर ये खोल दिया जाए तो इससे भी लाखों लोगों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय सांतवा है मेरा जो अभी मास्टर प्लान के अंदर अंकित कर दिया गया है और जल्दी से जल्दी इस रोड़ को बनाया जाए जो हैलीपैड से सीधा केएमपी पर जाना है और आठवां मेरा रोड़ है अध्यक्ष महोदय ये हमारा पीडब्ल्यूडी का रोड़ है अध्यक्ष महोदय जिसकी मैं बार बार सदन के अंदर मुद्दा उठाता हूं, बार बार मैं बताता हूं कि क्योंकि ये डेढ़ सौ साल पुराने रोड़ हैं और इन्हीं पर जो यातायात है वो इन्हीं पर चलता है जिसकी वजह से लगातार ट्रैफिक जाम रहता है लोग परेशान रहते हैं। अध्यक्ष महोदय इसको चौड़ा करने की बात है और गांव के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये रोड़ खुलना चाहिए क्योंकि साढ़े 82 फुट का रोड़ है अगर ये खुल जाए तो अध्यक्ष महोदय सभी को फायदा होगा। गांव के लोग अपने घर से उस रोड़ के उस पार भी नहीं जा पाते जिसमें जाम लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा कि एलजी साहब बार-बार, बार बार मेरी बवाना विधानसभा में कभी किराड़ी विधानसभा में बार बार जा रहे हैं लेकिन जो मैंने ये रोड़ बताए डीडीए के रोड़ अगर एलजी साहब इन पर ध्यान दे दें अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि बीस पच्चीस लाख लोगों को सीधा फायदा होगा लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं जा रहा उनके जो कार्य उन पर नहीं जा रहा

उनका जो कार्य है पब्लिक आर्डर जमीन दिल्ली पुलिस उस पर नहीं जा रहा। उनका ध्यान तो सिर्फ इस पर जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो काम चल रहे हैं उनको रोका जाए तो अध्यक्ष महोदय मेरा सदन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि एलजी साहब इन रोड़ों पर ध्यान दें जिससे कि आम जनता को इसका सीधा फायदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

माननीय अध्यक्ष: श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादव: धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मेहरौली एक ऐतिहासिक शहर है। कुतुब मीनार जो वर्ल्ड फेमस है। अध्यक्ष जी इस सदन में मैं काफी समय से मेहरौली के लिए पानी की समस्या का मुद्दा उठाता हुआ आया हूँ। अध्यक्ष जी, मेहरौली के अंदर पानी के लिए एक प्रोजेक्ट सटार्ट किया गया था 2012 में जब मैं 2015 में विधायक बनकर आया तो मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी वर्किंग की हालांकि उस समय तक ये प्रोजेक्ट पूरा बंद पड़ हुआ था। मैंने उस समय के माननीय मंत्री जी से मुलाकात की माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को ले के आया। माननीय मुख्य मंत्री साहब ने इस प्रोजेक्ट को go ahead किया और इस पे काम स्टार्ट हुआ लेकिन अध्यक्ष जी लगातार आज नौ साल हो गए हैं अभी तक ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पैण्डिंग पड़ा हुआ है। इसमें कंपनी को जो ये प्रोजेक्ट दिया गया था उसका नाम था एमवीवी, एमवीवी कंपनी को दस साल के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था लेकिन दस साल पूरे हो गए एमवीवी

कंपनी भी वहां से चली गई लेकिन आज करोड़ों रुपये की पैमेंट इस प्रोजेक्ट के उपर हुई है लेकिन वो सारा का सारा धरातल पर पैसा बर्बाद हुआ है और दिल्ली जल बोर्ड की डायरेक्टली इसमें मिली भगत रही है इस प्रोजेक्ट में, कभी भी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ये 2012 का है। उस समय हमारी सरकार नहीं थी उस समय जो भी इसके अंदर हुआ इसके उपर जांच भी हुई थी शायद इसमें सीबीआई का भी मामला आया था लेकिन क्योंकि मेहरौली के लोगों को पानी चाहिए था इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को चालू कराया लेकिन अध्यक्ष जी आज भी ये दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारी इस काम को पूरा नहीं करना चाहते। जब वो प्रोजेक्ट वाली कंपनी चली गई तो दिल्ली जलबोर्ड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को ये पूरा करना चाहिए इसमें चार यूजीआर बनने थे। तीन बन के भी तैयार हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं लाइनें नहीं डली, कहीं फीडर लाइन नहीं है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपये की पैमेंट होने के बाद भी आज अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा अध्यक्ष जी, वहां पर एक सीवर का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था दोनों साथ साथ ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे। सीवर में भी अलग अलग फेजीज में ये काम होना था। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री लेकिन फेज वन का काम भी आज तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है इसके लिए माननीय मंत्री उस समय सौरभ भारद्वाज जी थे उन्होंने भी मीटिंग की थी। मेरी रिकवेस्ट पे माननीय मंत्री साहब ने वो एमवीवी कंपनी को तो पूरी तरह से हटा दिया क्योंकि वो कामयाब नहीं थी वो कंपनी उसके बाद में वाइस चेयरमैन साहब हमारे सोमनाथ भारती जी ने

भी कई बार इसके उपर मीटिंग की है और कई बार वो एरिया विजिट करने भी आए हैं। अध्यक्ष जी, आज भी मेहरौली के अंदर कम से कम चार पांच दिनों में लोगों को पानी मिलता है। इस सदन में मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं कि पूरी दिल्ली में भी शायद ऐसी जगह नहीं होगी कि जहां इतने दिनों के बाद पानी मिलता हो तो आपसे हाथ जोड़ कर मेरी विनती है कि किसी भी तरह से और जलबोर्ड का भी ये कहना है कि जब तक ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होंगे क्योंकि लाइनें लगभग सत्तर अस्सी परसेंट डल चुकी हैं। यूजीआर भी सत्तर अस्सी परसेंट पूरे हो चुके हैं लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मेहरौली थोड़ा कंजस्टीड है, नैरो गलियां हैं वहां पर एकदम से ओपनली काम नहीं हो सकता तो अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस दोनों प्रोजेक्ट के मुद्दे को पेटिशन कमेटी में रेर किया जाए जिसमें कि वहां पर एक दबाव बने अधिकारियों पे, कुछ जांच हो जिससे कि ये मेरी इच्छा ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाए अगले एक साल के अंदर ताकि मेहरौली के लोगों को पानी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष: श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी एरिया की समस्या के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, कोटला मुबारक पुर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां हजारों लोग भीष्म पितामह रोड़ को पार करते हुए डिफेंस कालोनी की ओर

जाते हैं, ना केवल सर्विसिंग लोग, बल्कि महिलाएं और खास कर स्कूल के बच्चे डिफेंस कालोनी में तीन स्कूल हैं जो सरकारी हैं और कोटला के कई हजार बच्चे उस रोड़ को पार कर कर दूसरी तरफ जाने को बाध्य रहते हैं। महोदय काफी ज्यादा लंबा स्ट्रेच है और कोटला मुबारकपुर के निवासी जब इस रोड़ को पार करते हैं तो उन्हें लगभग एक किलोमीटर का स्ट्रेच है दोनों तरफ जहां बीच से अगर आप लें तो एक तरफ 500 मीटर दूसरी तरफ 500 मीटर पे लाल बत्तीयां हैं। एक तरफ रिंग रोड़ है और एक तरफ डिफेंस कालोनी का फ्लाई ओवर है। इस वजह से यहां लगातार चूँकि बीच में दीवार खड़ी है सड़क डिवाइडर के रूप में तो बच्चे या तो उसको बीच में से पार करते हैं, हमेशा एक्सीडेंट का खतरा लगा होता है और कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं 2020 में हमारी रिक्वेस्ट पर यहां एक एफओबी का निर्माण कार्य शुरू हुआ उसकी कीमत डेढ़ करोड़ रूपया थी जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो वहां अचानक नीचे सीवर की लाइनों का एक बड़ा ट्रंक सीवर लाइन निकल आई जिसकी वजह से वो फट गए और वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उस साईट को चेंज करने के लिए काफी मशक्कत की और जब उसके पड़ोस में ही खुदाई की तो वहां बिजली के बहुत बड़े तार का जंजाल तारों का जंजाल मिला सप्लाई disrupt हुई और कई दिन तक वो इलाका अंधेरे में डूबा रहा उसकी वजह से वो काम फिर रूक गया। इस काम को करवाते हुए पीडब्ल्यूडी ने चूँकि वहां बहुत ज्यादा जरूरत भी थी दूसरी तरफ डिफेंस कालोनी पे बने हुए एक बस स्टैंड को आठ नौ लाख रुपये

की कीमत से शिफ्ट भी किया पर अचानक चूँकि उसकी कीमत पौने दो करोड़ रुपये के करीब और एस्कलेट कर रही थी डेढ़ करोड़ का FOB बनता पौने दो करोड़ रुपये के करीब बिजली के तारों को बदलने का शिफ्ट करने का और सीवर की लाइनों को ठीक करने का बन रहा था, कोई लोग कोर्ट चले गए, माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पीडब्ल्यूडी ने उस प्रोजेक्ट को स्क्रेप करना पसंद किया और ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। महोदय, हमने बार बार अधिकारियों से रिकवेस्ट की है कि अगर वहां एफओबी फिजीबल नहीं है तो आप एक sump subway जिससे लोग आरपार पार कर सकें। ऐसा एक सबवे जो पैदल यात्रियों को एक कोटला की तरफ से डिफेंस कालोनी और डिफेंस कालोनी की तरफ से कोटला की तरफ ले आए वहां बनवाने की अत्यंत ज्यादा आवश्यकता है। ये ना केवल लोगों के हक में है बल्कि कई हजार बच्चे स्कूल गोइंग जो छठी क्लास से ले के बारहवीं तक के स्कूल के बच्चे हैं उनको जो रोज वहां अपनी जान की परवाह करनी पड़ती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि वो इसके बारे में संज्ञान लेकर वहां अति शीघ्र एक सबवे टाइप जो लोगों को आरपार करने की सुविधा प्रदान करे। वहां ऐसा एक सबवे बनवाने की कृपा करें। आपने मुझे मौका दिया, मंत्री जी ने सर हिलाकर सहमति जताई है। ये केजरीवाल जी के सारे मंत्री ऐसे ही हैं। ये जब भी कभी कोई बात होती है उस पे तुरंत काम करने के लिए तैयार रहते हैं और सहमति देने के बाद उसको कार्य को, नहीं एलजी हरेक की, एलजी हरेक काम

को नहीं रोक पा रहे हैं। हरेक काम को नहीं रोक पा रहे हैं। हरेक काम को नहीं रोक पा रहे हैं। हमारे मंत्री इतने prompt हैं न केवल वो सहमति दे देते हैं क्योंकि उनको जरूरत महसूस होती है और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री या हमारे सी.एम. साहब, ये लोग सड़क से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें वास्तुस्थिति का अच्छी तरह ज्ञान है, जैसे आपको ज्ञान है।

माननीय अध्यक्ष: चलिए धन्यवाद बहुत-बहुत।

श्री मदन लाल: आपको सारी दिल्ली का पूरा भौगोलिक, आपको सर पूरी भौगोलिक स्थिति जानते...

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद-धन्यवाद।

श्री मदन लाल: और ये रोड से सर, ये रोड से कई हजार मोटर व्हीकल्स गुजरते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और मुझे पता है कि उनके आश्वासन के बाद ये यहां सबवे अब तुरंत बन जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सोमनाथ भारती जी (अनुपस्थित)। श्री सही राम जी।

श्री सही राम: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के एक गंभीर विषय को लेकर बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां तुगलकाबाद विधान सभा में एक लाल कुंआ बहुत बड़ी बस्ती है, तकरीबन 60-70 साल

पुरानी बस्ती है, वहां लगभग 2 वर्ष पहले BSES ने बिजली के कनेक्शन काटे हैं। ये मैंने मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया था। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक खोरी गांव था उसको तोड़ा गया, खोरी गांव हरियाणा में था, लाल कुंआ दिल्ली का हिस्सा है, ये बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा की बिल्कुल सीमा के साथ सटे हुए हैं, आपस में लोगों के मकान भी मिले हुए थे। तो जब खोरी गांव को तोड़ा गया अध्यक्ष महोदय उस समय BSES ने ये कहकर यहां के कुछ कनेक्शनों को काट दिया कि कोई दुर्घटना न हो जाए। जैसे ही खोरी गांव का डेमोलिशन पूरा होगा, आपको तुरंत ये ही मीटर, ये ही कनेक्शन दोबारा रिलीज कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 साल हो गए उन लोगों को बिजली विभाग के धक्के खाते-खाते, मेरी कई बार मीटिंग भी हुई, मैंने मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया, अब मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, मेरा इनसे निवेदन है करीब-करीब 300 ऐसे लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, अब वो उनसे रजिस्ट्री मांगते हैं। अब रजिस्ट्री बंद है तो वो रजिस्ट्री लाए कहां से, एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरा अध्यक्ष महोदय कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कभी कांग्रेस के शासन काल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में वहां एससी/एसटी के लोगों को प्लॉट दिए गए थे, आज उनको भी बिजली के कनेक्शन बंद कर रखे हैं, बहुत परेशानी है। कई लोगों पर theft के मामले बना दिए। अध्यक्ष महोदय, बिजली एक ऐसी चीज है जिसकी हर आदमी को जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं इनसे निवेदन है कि वहां उन लोगों को जल्द से जल्द कनेक्शन उनके रिलीज कराए जाए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री राजेंद्रपाल जी।

श्री राजेंद्रपाल गौतम: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और विशेष रूप से माननीय मंत्री-पीडब्लूडी, आतिशी जी का ध्यान अपनी विधान सभा की मुख्य रूप से 2 समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा में जो डीसी ऑफिस है-नंद नगरी, उसके सामने ई ब्लॉक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और जीटीबी एंक्लेव में भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और पूरे जिले से चूँकि 2 जिलों का ये डीसी ऑफिस है, पूरे जिले से, दोनों जिलों से हजारों लोग रोज डीसी ऑफिस में कास्ट सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट, survivor certificate या अन्य रजिस्ट्री वगैरह के काम से डीसी ऑफिस आते हैं लेकिन वहां रोड क्रॉस करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या दोपहर को छुट्टी होती है, दोनों स्कूल के बच्चे, हजारों बच्चे चूँकि सुंदर नगरी के बच्चे उधर जीटीबी एंक्लेव में भी पढ़ते हैं और ई ब्लॉक के स्कूल में भी पढ़ते हैं। साढ़े आठ साल से मैं वहां फुटओवर ब्रिज बनाने की डिमांड कर रहा था। सत्येन्द्र जैन जी ने उसमें इंटरेस्ट लिया और चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ को साथ में लेकर दो-तीन बार की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा यहां फुटओवर ब्रिज नहीं स्काई वॉक सक्सेस होगा, उन्होंने पूरा डिजाइन बनाया लेकिन उसके बाद भी वो काम आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद ये विभाग माननीय मनीष सिसोदिया जी के पास आया। उन्होंने भी उन अधिकारियों को बुलाकर बेहद सख्ती से लिया और उसके बाद उसकी स्टडी करवाई गई। स्टडी में एक्सपर्ट ने कहा कि हां ये बिल्कुल

फिजीबल है और बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी के माध्यम से भी कोशिश हुई और अब आतिशी जी हैं। मेरा मन इतना दुखी है कि साढ़े आठ साल में एमएलए रहते हुए और साढ़े पांच साल मंत्री रहते हुए मैं ये छोटा सा काम करवाने में असफल रहा हूं और इससे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि वो सुंदर नगरी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल जी का कर्मक्षेत्र रहा है, उस कर्मक्षेत्र के साथ इतना सौतेला व्यवहार इन अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है, बार-बार क्वेरी लग रही हैं, बार-बार क्वेरी लग रही हैं, आखिर कब तक क्वेरी लगेंगी। कई बार तो मन करता है मैं विधायक की इस सीट से इस्तीफा दे दूं क्योंकि इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि एक मतलब इतना सा काम मैं करवाने में सफल नहीं हो पा रहा हूं और वो भी बच्चों, जहां से बच्चे क्रास करते हैं, इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती, इनको दिखता नहीं है कि वहां से बच्चे क्रास करते हैं और हजारों लोग सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं। क्या कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो माननीय अध्यक्ष जी मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी से, मंत्री जी से मेरी पीछे बात भी हुई है उन्होंने कहा भी है मैं अधिकारियों को बुलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस कार्यकाल में इस काम को तो शुरू करवा दो, इतना काम तो हो जाए।

.....व्यवधान.....

श्री राजेन्द्र पाल गौतम: नहीं, वो तो मैं जानता हूं, अधिकारी तो सारे, हमारे एल.जी. साहब के अधिकारी ही तो काम अटका रहे हैं और मुझे लग रहा है इसलिए ज्यादा अटका रहे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री

जी का कर्मक्षेत्र है, तो इसका बदला सुंदर नगरी के, नंद नगरी के, सीमापुरी के लोगों से क्यों ले रहे हैं मेरी ये समझ नहीं आ रहा।

और दूसरा मसला इसी में, नंद नगरी में तांगा स्टैंड रोड और मेरी और आपकी विधान सभा के बीच डिवाइडर रोड, यहां 40 साल पुराने ईंटों के नाले बने हुए हैं वो नाले पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। चीफ इंजीनियर सहित सारे अधिकारियों को लेकर मैं विजिट कर चुका हूं कि इसका कंक्रीट का नाला बनवा दो, ये मांग भी मैं पिछले करीब 6 साल से कर रहा हूं और सारे इंजीनियर कह रहे हैं जी ईंट का नाला ये बेकार हो चुका है, ये सफल नहीं हो सकता है, कंक्रीट का नाला बनना चाहिए। इंजीनियर भी मान रहे हैं बनना चाहिए। सबको लेकर कई बार विजिट कर चुका हूं सारे अधिकारियों को लेकर लेकिन बार-बार एस्टीमेट जाता है और कोई न कोई क्वेरी लेकर वापस आ जाता है। क्या ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी-पीडब्लूडी का ऑफिस इस काम के लिए बना है कि वहां बैठे हुए इंजीनियर उसमें क्वेरी लगाते रहें। आपको जानकर दुख होगा और आपकी विधान सभा के भी जो बी ब्लॉक है या जो ई ब्लॉक और इधर के जो पॉकेट्स हैं उनमें भी इसी तरह के फ्लैट्स हैं जो डीडीए के बनाये हुए फ्लैट हैं, 40-40 साल से ज्यादा पुराने बने हुए हैं, वहां, उनके अंदर का पानी नाले से होकर बाहर नहीं जाता, जीटी रोड वाले नाले में नहीं मिलता, वहां उनका पानी उन मकानों के नींव में जा रहा है, मकानों की हालत जर्जर हो रही है, कल को वो मकान अगर गिर जाए चूंकि जब नींव कमजोर होती जा

रही है और कल को वो मकान गिर गए तो कितने लोग उसके अंदर मरेंगे, ये आपकी विधान सभा की भी स्थिति है, मेरी भी है।

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं ये केवल 2 नाले हैं, एक तांगा स्टैंड रोड का नाला नंद नगरी का है और चूँकि वो नाला भरा रहता है और पीछे से वो पानी जा नहीं पाता तो गलियों में पानी निकला रहता है, उधर इन पॉकेट्स में पानी भरा रहता है तो इतने दिन से कोशिश करने के बाद भी ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से एल.जी. साहब से भी निवेदन करता हूं पूरे दिल्ली में वो विजिट कर रहे हैं, इधर बुराड़ी में भी पहुंच गए, उधर किराड़ी में भी पहुंच गए, मैं तो उनका स्वागत भी करूंगा ढोल-नगाड़े के साथ, एक बारी नंद नगरी, सीमापुरी, सुंदर नगरी भी तो आकर विजिट कर लें।

आप लोग एक अवैध कब्जे नहीं हटवा पा रहे हैं। पीडब्लूडी के रोड कब्जे होते जा रहे हैं, डीडीए के पार्क कब्जे होते जा रहे हैं, डूसिब के पार्क कब्जे होते जा रहे हैं, एमसीडी के पार्क कब्जे होते जा रहे हैं, सारे पीडब्लूडी के फुटपाथ कब्जे होते जा रहे हैं। क्या ये कब्जे हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे? कंक्रीट के नाले कभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये स्काई वॉक कभी बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं इन मुद्दों से बेहद दुखी हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये बात एल.जी. साहब तक जाए कि वो अपने अधिकारियों को निर्देश दें, जो क्वेरी जितनी लगानी है एक बार लगा दें ताकि उनकी क्वेरी रिप्लाइ हो जाएं। तीन क्वेरी लगती हैं, एक क्वेरी रिप्लाय करते हैं इंजीनियर, अगली बार दूसरी क्वेरी लग जाती है, इसका

मतलब इनकी नीयत काम करने की नहीं है, काम को लटकाने की है, सरकार को बदनाम करने की है और ताकि हम लोग, एमएलए लोग भी अपने-अपने क्षेत्र में बदनाम हो जाए कि ये एमएलए काम नहीं करवा पा रहें। तो मैं चाहूंगा कि इसको बेहद गंभीरता से लिया जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो ये इशू मैं आज रेज कर रहा हूँ ये इशू मैं कम से कम चौथी बार जो है इस सदन के सामने, इस विधान सभा के सामने जो है रेज कर रहा हूँ। और मेरे क्षेत्र में निजामुद्दीन में एक स्कूल बनना है जिसका मुद्दा जो है मैं कई समय से जो है इस सदन के माध्यम से उठाता रहा हूँ लेकिन चार बार उठाने के बावजूद जो है उस समस्या का निष्कर्ष जो है वो आज तक नहीं निकला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि अफसरों द्वारा ऐसी लॉबी बना दी गई है कि जो काम हो सकते हैं उन काम को भी लगातार जो है रोका जा रहा है। ये समस्या जो है वो चौथी बार मेरे उठाने का यहां पर प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो है मेरी इस समस्या का समाधान जो है, हल जो है वो जरूर निकलेगा। दिल्ली जल बोर्ड के पास एक जमीन है और उस जमीन में मैंने स्कूल बनाने का प्रपोजल दिया हुआ है क्योंकि उसके पास जो है, उस क्षेत्र के आसपास जो है कोई स्कूल

वहां पर नहीं है और लोगों को, बच्चों को जो है बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है तो मैंने वहां पर प्रपोजल दिया है कि छठवीं से बारहवीं तक का स्कूल जो है वहां पर बनाया जाए। और जल बोर्ड ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लिखकर दे दिया है कि हां आप वहां पर स्कूल बना सकते हैं। लेकिन जब ये मसला डीडीए में गया उस दौरान पता लगा कि ये जमीन जो है वो रिक्रिएशन के लिए एलॉटेड है और उसके कारण जो है वो सैम एमाउंट की लैंड जो है वो जल बोर्ड को डीडीए को हैंडओवर करनी है। पिछली बार जल बोर्ड में भी मीटिंग हुई, अधिकारियों ने अपनी गर्दन हिला दी लेकिन आज तक जो है उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये पीड़ा है, ये पीड़ा है, गर्दन तो हिला देते हैं लेकिन वो काम नहीं होता। एक बार मीटिंग हुई, दो बार मीटिंग हुई, तीन बार मीटिंग हुई, लेकिन आज तक जो है वो ये काम जो है वो संपन्न नहीं हो पाया।

मैंने पिछली विधान सभा में, अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली विधान सभा में एक प्रश्न लगाया था 15/12/2023 को, जिसमें मैंने इस मामले की अपडेशन जो है उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जाननी चाही और मैंने जो प्रश्न लगाया कि जो जल बोर्ड द्वारा जो लैंड जो है इक्वल एमाउंट की लैंड जो है डीडीए को देनी थी क्या वो लैंड दे दी गई, तो उस प्रश्न का जवाब ही नहीं आया बल्कि और कोई जवाब उन्होंने दे दिया, जो एक जॉइंट मीटिंग हुई थी एक साल पहले, उसका जवाब जो है दे दिया। ये अधिकारी जो हैं ये सदन को मूर्ख समझते हैं, यहां पर बैठे हुए लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश

करते हैं, उन्हें लगता है ये चौथी पास लोग हैं लेकिन यहां पर जो है वो पढ़े लिखे लोग जो हैं इस सदन में बैठे हुए हैं, अधिकारियों को नहीं पता। अब ये अधिकारी जो होने वाले काम हैं उन्हें भी अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लॉबिंग जो है वो अधिकारियों के माध्यम से अध्यक्ष महोदय यहां पर बन गई है जिसको जो है हमें तोड़ना और हमें जो है उनको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन पटल पर मैं इस प्रश्न को जो है और उसके जवाब को यहां पर रखना चाहूंगा और मेरी गुजारिश है कि यहां पर इस मेरे प्रश्न को जो है प्रिविलेज कमेटी में रेफर किया जाए। एक और मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से अधिकारी जो हैं वो लगातार जो है हमारे कामों को रोक रहे हैं, लगातार जो होने वाले काम हैं उनको भी रोक रहे हैं। एकआध अधिकारियों को आप जेल में भेजकर देखिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए भेजकर देखिए, अपने आप ये अधिकारी सब सही हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये आपके माध्यम से इस सदन पटल पर इस प्रश्न को रख रहा हूं और मुझे आशा है कि इस मेरे मसले का समाधान जरूर निकलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार आम आदमी के पक्ष में काम करती चली आ रही है और उसी का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि तीन बार दिल्ली में, उसके बाद एमसीडी में, पंजाब में हमें बहुत प्यार और सम्मान मिला। मैं क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी जो

बात करते थे कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, बात तो इन्होंने कर दी, करा कुछ नहीं। लेकिन उस अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जो लेबर है, जो फैक्ट्रियों में काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है उसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आईं। हम अगर उसकी शादी होती है जो काम करने वाला है उसके बच्चे की तो लड़के की शादी में 35 हजार रुपये देते हैं, लड़की की शादी में 51 हजार रुपये देते हैं। मैटरनिटी लीव पर 30 हजार रुपये देते हैं, भगवान न करें उस बच्चे में कोई दिक्कत हो जाए तो भी उसमें भी वो पैसे हम देते हैं मैटरनिटी में। डेथ पर एक लाख रुपये देते हैं। और पेंशन के तौर पर हम उसे 3 हजार रुपये देते हैं जब वो 60 साल की उम्र पर पहुंच जाता है और हर साल उसमें 10 परसेंट बढ़ोतरी भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार है जो उस पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचा रही हूं। अब इन्होंने उस पर कैसे अडंगा लगाया कि आज अगर आप वो लेबर कार्ड बनाने जाओ, क्योंकि और कोई चीज नहीं चाहिए सिर्फ एक लेबर कार्ड चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको बनाने में भी ये दिक्कतें पैदा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने सबको इतना फायदा दे दिया, ये तो बहुत फायदा मिल जाएगा एक गरीब आदमी को, तो आज वो कार्ड बनाने जाता है तो उस लेबर कार्ड को ही नहीं बनने देते ये, बस इतना ही बनवाना है, वो ही नहीं करने दे रहें। और वजह क्या, मैंने उनसे मीटिंग करी, तो वजह क्या लेकर आ रहे हैं कि सर आप जो भेज रहें हो न, पहले हमारे पास में कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर था, हम नाम डालकर देख

लेते थे, आपने किसको भेजा है, बिधूड़ी जी ने किसको भेजा है, किसने किसको भेजा है तो उसका हम कर देंगे। अरे क्यों भई, आप किसी का क्यों नहीं बनाते हो, जो, अब यहां से जाते हैं हमारे ऑफिसिस से, पांच मिनट में उसका रिजेक्शन भेज देते हैं, पांच मिनट में, कितनी तेजी से काम हो रहा है ताकि वो गरीब आदमी बार-बार परेशान हो और धक्के खाए या तो पैसे देने की बात करे या विधायक के पास आ जाए। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों पर कोई न कोई नकेल कसी जाए, जो इतने गरीब आदमी को जो उनके पास में धक्के खा रहा है, उसके पास समय नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा दिहाड़ी कमा रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए और पूरी तरीके से सख्ताई करी जाए। अगर अधिकारी चाहते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव करा जाए, आप कर दें, तो आपके माध्यम से ये मेरा सुझाव था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, तीन विभाग और तीन सब्जेक्ट मैटर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, ये तीनों आर्टिकल 239 एए के अंतर्गत सेंट्रल गवर्मेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्मेंट में नुमाइंदगी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट करता है। अध्यक्ष महोदय, डीडीए के पार्को में जिस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं, जिस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, ड्रग पेडलिंग हो रही है, इसका दायित्व रोकने का पुलिस के पास है। मेरे क्षेत्र में

सतपुला पार्क है, विजय मंडल पार्क है, हुमायूँपुर के अंदर पार्क है, इस प्रकार के ऐसे कई प्रकार हैं जिसमें अनगिनत वारदात ड्रग पेडलिंग के हुए हैं, ड्रग कंजम्पशन के हुए हैं, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के हुए हैं, लेकिन इन सारे कामों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे साथी सदन में जो उपलब्ध हैं, वो इस बात से राजी होंगे कि पुलिस की जो जिस प्रकार से निष्क्रियता है क्राइम के प्रति। दिल्ली में 7 सांसद हैं भाजपा के लेकिन एक भी सांसद ने एक भी बार दिल्ली की जनता के लिए उन विभागों पर भी काम नहीं किया जो विभाग उनके पास हैं। मतलब अनगिनत समस्याएँ हैं जहाँ कि जनता को पता नहीं कि भई कहाँ जाए, आखिर जाती है हमारे पास। जो विधायकगण हैं, जो एक्सेसबल हैं, जो ट्रेसेबल हैं, जो कैचेबल हैं वहाँ तो उनका पहुँच है, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ एल. जी. साहब के पास कि सातों सांसद पूरे निष्क्रिय हैं, पाँचों साल एक काम नहीं किया, उन मसलों पर भी जो मसले उनके पास थे। मेरे यहाँ, मेरी विधान सभा में ऐसी कई वारदात हो गए, मेरे विजय मंडल पार्क में जो डीडीए का पार्क है, डीडीए भी सांसद के पास, पुलिस भी सांसद के पास लेकिन जो क्राइम घटता है, डीडीए में दिन-दहाड़े, 12 बजे दिन में एक लड़की को एक लड़के ने रॉड से मार डाला लेकिन कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा। सांसद नहीं पहुँचा, कोई भाजपा का नेता नहीं पहुँचा, वहाँ पर समय से पुलिस नहीं पहुँची, डीडीए के अधिकारी नहीं पहुँचे तो जनता जाए तो कहाँ जाए अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से इस बात को चाहता हूँ कि एलजी साहब तक पहुँचे, वीसी डीडीए

तक पहुंचे, पुलिस कमिशनर दिल्ली तक पहुंचे। मेरे यहां सतपुला पार्क है वहां करीब 5-6 बजे शाम को 15 साल के बच्चे को मार दिया। मैं बता रहा हूं तो वो जो इंसीडेंट मेरे यहां घटी है उस इंसीडेंट का हवाला मेरे ख्याल हर तरफ हर विधानसभा के अंदर है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां की पुलिस की बात है कभी वहां सांसद पहुंचा होगा। उसका कारण एक ही है जो मेरी सांसद हैं उन्होंने कहा एक दिन हाइकोर्ट के अंदर मैं मिला मैंने कहा मैडम 5 साल, 10 साल आपको हो गये अब सांसद हुए कुछ काम-वाम कर लें इसमें जनता पूछ रही है। कह रहे हैं सोमनाथ जी गलतहफहमी है आपको, काम के बल पर वोट आप मांगिये हमको तो वोट मिलता है मोदी जी के नाम से। लेकिन इस बार जनता राजी है, इस बार दिल्ली की जनता राजी है उन सारे सांसदों को, भाजपा के सांसदों को दिल्ली की जनता हराकर मानेगी क्योंकि उन्होंने अपने काम तो किये ही नहीं खासकर के अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने का प्रयत्न किया। कभी भी दिल्ली की आवाज न बन सके वो पार्लियामेंट में, दिल्ली की समस्याओं की आवाज न बन सके पार्लियामेंट के अंदर और इन्हीं कारणों से इस बार अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि आप इस बात को साफ-साफ पहुंचा दें कमिशनर साहब को भी जो पुलिस के कमिशनर हैं, वीसी डीडीए को भी और जो सबके सर्वा हैं एलजी महोदय वहां तक पहुंचा दें। आपने मुझे बात रखने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: भावना गौड।

सुश्री भावना गौड: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस विषय पर चिंता करूंगी कि दिल्ली के युवाओं की स्थिति बड़ी अपने आप में चिंताजनक है और ये बात पूरी दिल्ली पर लागू होती है मेरी विधानसभा पर ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भारी मात्रा में ड्रग्स की जो बरामदगी अभी तीन-चार दिन पहले हुई है वो अत्यंत चिंताजनक है। यह बरामदगी यह दर्शाती है कि यहां पर कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की आपूर्ति की जानी थी। पुर्ण पुलिस ने पुणे में ड्रग्स बरामद करने के बाद गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली में कोटला मुबारकपुर और मस्जिद मोठ के इलाके में स्थिति दो गोदामों से 970 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की है। मैफेड्रोन जिसे म्याउं-म्याउं ड्रग्स भी कहा जाता है उसकी इतनी बड़ी बरामदगी के साथ ही दिल्ली से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, उसे हिरासत में लिया गया। यह व्यक्ति एक कुरियर कंपनी से संबंध रखता था जिसके जरिये फूड पैकेट में ड्रग्स की आपूर्ति की जाती थी। अध्यक्ष महोदय, इस बरामदगी में यह सामने आया है कि आरोपियों ने ड्रग्स रखने के लिए नमक कारोबारी बनकर दो दुकानें किराये पर ली थी। यही नहीं किरायेदारों का पुलिस के द्वारा सत्यापन भी किया गया था इसके बावजूद आरोपी पुलिस की नजरों में नहीं आए। ड्रग्स की इस बरामदगी से दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। प्रश्न उठता है कि ड्रग्स की इतनी बड़ी मात्रा में भंडारण की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी और दूसरा वही किरायेदार के सत्यापन के बावजूद वह पुलिस से बचने में कैसे सफल हो गये। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस के इस संजाल

को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है कि एलजी साहब को भी कदम उठाना चाहिए। ये उनका अपना विभाग है और उनके अपने विभाग के अंदर जिस काम को वो बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं और दिल्ली के युवा अपने आप में एक बड़ी भयानक स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से एलजी साहब को यह कहना है कि वो पुलिस को ये जो नेटवर्क दिल्ली के अंदर चल रहा है ड्रग्स का इसको पूरी तरह से वो खंगाले, दिल्ली को बचाएं, दिल्ली के युवाओं को बचाएं और ये जो उपलब्धता दिल्ली के अंदर ड्रग्स की है इसको जड़ से खत्म करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी साथियों ने भी कहा है कि किस तरह की एलजी साहब का इंटरफेयरेंस डे-टू-डे जो चाहे वो एजीक्यूटिव वर्क हो या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या बाकी विधानसभा में जो इंटरफेयरेंस उनका बढ़ता जा रहा है मैं उसकी तरफ आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले एलजी साहब बुराड़ी विधानसभा में आए। जब वो विधानसभा आए इसकी जानकारी मुझे नहीं थी बाद में अफसरों के जरिये मुझे जानकारी मिली। उससे 6 महीना पहले मैं एलजी साहब से मिला था और अपनी विधानसभा की जो बर्निंग इश्यू है वो हमने उनसे मिलकर शेयर किया था। सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू हमारे यहां लॉ एंड आर्डर का है। रोज चोरियां हो रही हैं कई तरह के और अपराध हो रहे हैं। हर कालोनी में 10-20 ड्रग्स का कारोबार हो रहा है

तो हमने उनको कहा था कि इस पर एक ठोस काम किया जाए ताकि एक एग्जाम्पल साबित हो। दूसरा हमारे यहां जो अब ग्रामसभा की जमीन है जबसे अर्बनाइज हुआ वो डीडिए के अधीन चला गया है। अब डीडिए के अधीन जब से गया है तो उस पर इनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है तो हमने डिटेल्ड खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्रामसभा की जमीन पर कब्जा हो रहा है उस पर उनको कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर ये बहुत बर्निंग इश्यू है। तीसरा हमारे यहां अब अनॉथराइज कालोनी में एक आर्डर डीडिए ने निकाल दिया जिसमें कहा कि अनॉथराइज कालोनी में अब बिजली जो लगेगी उसमें डीडिए का एनओसी चाहिए। अब पूरी विधानसभा में लोगों को बिजली नहीं लग पा रही है हमने इसको भी उनसे शेयर किया था और उसके बाद अब हो ये गया है कि डीडिए एनओसी तभी देती है जब पचास हजार एक लाख रुपया उसको दे दिया जाए। तो भारी करप्शन और लोगों में बड़ा असंतोष है। तो जब एलजी साहब आए मुझे लगा कि मैंने जो उनको समस्या दी थी उस समस्या का शायद संज्ञान लेने के लिए हमें नहीं बताया कोई बात नहीं है वो उस विषय का संज्ञान लेने आए होंगे। लेकिन उनके आने के बाद जब उनकी मिनट्स आफ मीटिंग हमने देखे तो मिनट्स आफ मीटिंग में वो इस बात की जानकारी ली कि फ्लड इरिगेशन किस-किस कालोनी में काम कर रही है। सीवर किस गली में कितना बिछा है कितना नहीं बिछा है। पीडब्लूडी सड़क की सफाई कर रही है या नहीं कर रही है। उन्होंने फोटो डाला बाद में उनका मैंने ट्वीट देखा जो बड़ा ही सरप्राइजिंग है।

उन्होंने लिखा की 'Visited Burari. Replete with showrooms of top brands, the area comprising 80 Unauthorized Colonies, yet severely lacks basic amenities & civic infra that people are entitled to. Lakhs of residents remain deprived of roads, sewerage & sanitation. Governance must exceed postering.' अब जरा बताइये एलजी महोदय कि गवर्नमेंट कौन है? आपने तो केन्द्र सरकार ने एक्ट में कह दिया fdGovt. of Delhi means LG. तो क्या एलजी साहब अपने खुद के बारे में कह रहे हैं या वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अगर एलजी साहब को ये बेसिक भी समझ नहीं है या वो अपने एक्ट को भी नहीं जानते हैं तो फिर पावर को मिसयूज कर रहे हैं। हमारे एक कालोनी में जाकर एक-एक गली घूमे मैंने कालोनी वालों को बोला की किसी से मुलाकात हुई बोला साहब हमें तो नहीं लगा कोई एलजी साहब हमें लगा कोई जिल्लेइलाही आया है जिसके पीछे 100-200 सिक्वोरिटी थी दूर तक फटकने नहीं दिया जा रहा था हमें। तो मुझे यह लगता है कि अगर एक जनप्रतिनिधि को बिना बताए आप जाते हैं तो ये जो कांस्टीट्यूशन ने ये जो जनतंत्र ने जो चुने जनप्रतिनिधि को पावर दी है उसे आप सुपरसीड कर रहे हैं और इस तरह की डेली आर्डर अधिकारियों की मीटिंग्स बुलाकर के देना आप एक गवर्नमेंट के पावर को भी आप खत्म कर रहे हैं। तो एलजी साहब कौन सी राजनीति कर रहे हैं फिर और इस राजनीति से किसका फायदा होना है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को फिर संज्ञान दिलाना चाहता हूं क्योंकि हमने उनको कहा था कि अगर काम न हो तो एक महीने बाद फिर बुला लीजिएगा

उन्होंने कहा जी मैं बहुत व्यस्त हूं। अब पता चला वो व्यस्त इसलिए हैं कि बुराड़ी में, बवाना में, किराड़ी में अलग-अलग विधानसभा में वो गली-गली घूम रहे हैं। अरे जाकर थाने-थाने जाओ बदतर हालत है लॉ एंड आर्डर का। हर जगह ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। उसको जो आपके डीडीए कब्जा कर रही है वो तो आप कर नहीं रहे, आप ख्रामखाह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर राजनीति करते हैं। इससे एलजी पद शर्मसार हो रहा है और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं फिर संज्ञान देना चाहता हूं जो तीन बर्निंग इश्यू मैंने आपको दिये थे कि बुराड़ी विधानसभा में डीडीए के कारण बिजली नहीं लग रही है, ग्रामसभा की जमीन कब्जा हो रही है और लॉ एंड आर्डर और ड्रग्स का बड़ा कारोबार है उसको ठीक कराएं तो लोग आपको दुआएं देंगे और आप इस तरह की गंदी राजनीति से बचेंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: राजकुमारी ढिल्लों जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो: धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरी विधानसभा में मायापुरी जेजे क्लस्टर में फेज-1, फेज-2 तकरीबन वहां पर 15 से 20 हजार जेजे क्लस्टर के निवासी रहते हैं। हम उनको पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, फ्री चिकित्सा दे रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं जो उनकी एक मूलभूत आवश्यकता है उनकी टॉयलेट की समस्या चल रही है तो वहां तकरीबन 30 से 40 साल पुराना मायापुरी फेज-1 में ए-11-12 में एक जेएससी बना हुआ है लेकिन अध्यक्ष जी वो इतना जर्जर हालत में हो चुका है और पीछे 7 से 8 महीने पहले जो हमारे

डूसिब के सीईओ हैं उनके साथ दिल्ली जलबोर्ड के मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी लेकिन जो वो जेएससी बना हुआ है वो बिलकुल क्लस्टर के बीचों बीच है और उसमें जो हमारी प्रीफैब टॉयलेट बने हुए हैं दरवाजे बने हुए हैं प्रीफैब वो बिलकुल जर्जर हालत में हो चुके हैं। इतनी हम फेसिलिटी दे रहे हैं लेकिन एक मूलभूत अध्यक्ष जी आवश्यकता है उनके शौचालय की जिससे की कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि रेलवे लाइन फेज-1, फेज-2 की मायापुरी की वहां जवान यंग लड़कियां शौचालय के लिए चली जाती हैं कई हादसे भी हुए हैं। इन बातों को देखते हुए तकरीबन डूसिब सीईओ के साथ एक मीटिंग भी रखी थी 8 महीने पहले लेकिन उस प्रीफैब जेएससी को जिसके की जितनी सीट हैं उसमें दरवाजे हैं वो बिलकुल एकदम टूट चुके हैं और सीईओ के साथ मीटिंग रखने के बावजूद भी अभी तक जो हमारा प्रीफैब जेएससी है उसको पक्के शौचालय का काम हमारा अभी तक नहीं बना है। मैं आपके माध्यम से डूसिब के सीईओ से कहना चाहूंगी कि हम लोग इतना अच्छा जेजे क्लस्टर में हम काम कर रहे हैं। उन्हें हम पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर कुछ उनको फेसिलिटी है लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है शौचालय की खासतौर से महिलाओं के लिए उसको बहुत जल्दी उसको करवाया जाए क्योंकि कभी न कभी किसी प्रकार का वहां पर हादसा हो सकता है। तो मेरी आपके माध्यम से डूसिब के सीईओ और मंत्री साहब से मेरा निवेदन है की इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको तुरंत बनवाया जाए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: श्री पवन शर्मा जी।

श्री पवन शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधानसभा में पीडब्लूडी डिपार्टमेंट की तरफ दिलवाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पीडब्लूडी के नाले पूरी जहांगीर पुरी, कुशल सिनेमा रोड बोलते हैं उसको इतने भरे हुए हैं सिल्ट से कि नीचे थोड़ा-थोड़ा पानी चलता है ऊपर पेड़ उग गये हैं उसके कूड़े के ऊपर आदमी खड़ा भी हो जाए उस पर तो भी नहीं बैठता वो जो है कूड़ा। और धोबीघाट से कुशल सिनेमा और शाह आलम बंध रोड से मंगल बाजार रोड बोलते हैं इसको मंगल बाजार चौक तक और शाह आलम बंध के नाले पूरी तरह ब्लॉक हैं जिसकी वजह से कालोनियों में जो गलियां हैं छोटी नालियां हैं उन नालियों का पानी नाले में नहीं पहुंच पाता क्योंकि वह ओवरफ्लो हैं सारे सिल्ट से भरे हुए हैं तो गलियों में पानी भरा रहता है चौबीसों घंटे हर रोज सैकड़ों महिलाएं आदमी आफिस में कंप्लेंट लेकर आते हैं। पिछले 4 महीने से लगातार मैं बोल रहा हूं अधिकारी कभी किसी कोने में जेसीबी खड़ी की और उसकी फोटो खींचकर डाल दी की जी सफाई हो रही है लेकिन प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जो है प्रार्थना करता हूं की कृपया मेरे क्षेत्र में आदर्श नगर में इसको संज्ञान में लिया जाए और अधिकारियों को आदेश दिये जाएं की पीडब्लूडी के जितने भी नाले हैं उनको अच्छी तरह से साफ किया जाए। जहांगीर पुरी ए-ब्लॉक, जी-ब्लॉक और एच-ब्लॉक पूरी

कालोनी की गलियां जो हैं पानी से भरी रहती हैं, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान बिधूड़ी जी।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 280 में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मीठापुर विस्तार में गगन विहार के सामने एक एकड़ जमीन 2008 में 100 बिस्तरों के अस्पताल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को अलॉट की। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित ने उस हास्पिटल की नींव रखी। 2008 का यदि बजट उठाकर देखेंगे बजट प्रस्ताव तो बजट में भी हास्पिटल बनाने के लिए पैसे का प्रावधान किया गया लेकिन आज तक उस एक एकड़ जमीन पर अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। मैं निरंतर इसको लेकर सरकार के साथ बातचीत करता रहा हूं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पांच वार्ड्स हैं और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो नहर पार का एरिया है जिसमें हरि नगर वार्ड है, जैतपुर वार्ड है, मीठापुर वार्ड है उसमें कोई हास्पिटल ही नहीं है और ज्यादातर लोग मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग बेचारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं गरीब लोग हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जब जमीन अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध हो गई है और उस जमीन की चारदीवारी करा दी है वो जमीन खाली पड़ी हुई है तो उस जमीन के

ऊपर 100 बिस्तारों का अस्पताल बनाया जाए क्योंकि 2008 में जो बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया हास्पिटल बनाने के लिए बजट भी उपलब्ध करा दिया गया। अब क्या कारण है कि उस जमीन के ऊपर हास्पिटल नहीं बन पा रहा है। मैं आपके माध्यम से जरूर मांग करूंगा। यहां हमारे हाउस में सभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी, ये विषय आपके 280 में नहीं है।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): मैं कहता हूं इससे जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं इससे जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: ये बिधूड़ी जी जो बोल रहे हैं ये डिलीट कर दिया जाए उसमें से प्लीज।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): देखिये ये बहुत सारे ऐसे हैं जो।

माननीय अध्यक्ष: जो 280 में हैं।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: उस विषय को उससे बाहर मत लीजिए।

¹ चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गये।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: राजेश जी बैठिये मैं रोक रहा हूँ न, मैं रोक रहा हूँ न, आप बैठिये। मैंने बोल दिया की ये डिलीट कर दीजिए बस।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी बैठिये प्लीज।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: बैठिये आप बैठिये।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी बैठिये, आप समझदार हैं समझते हैं सब चीजें, बैठिये प्लीज, प्लीज बैठिये।

श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx¹

माननीय अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: माननीय उपराज्यपाल के भाषण पर चर्चा। 16 फरवरी, 2024 को माननीय विकास मंत्री गोपाल राय जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे श्री राजेश गुप्ता जी।

¹ चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गये।

श्री राजेश गुप्ता: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा है दरसल, सच बताऊं तो एक ऐसा दिन होता है जब माननीय उप-राज्यपाल जी यहां आते हैं कि जिस तरीके से बच्चे अपने एनुअल डेज के फंशंस का इंतजार करते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने उस साल के अंदर क्या-क्या करा और अच्छे बच्चों को अवार्ड्स मिलते हैं। तो जब माननीय उप-राज्यपाल जी यहां आते हैं और बताते हैं कि दिल्ली की सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां हैं और आगे वो क्या-क्या करने जा रही हैं तो हमें बहुत मजा आता है। तो जब वो बार-बार बोलते हैं कि मेरी सरकार ने ये करा तो और ज्यादा मजा आता है। इस बार हालांकि ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही दुखद था कि जब उप-राज्यपाल जी बोल रहे थे तब हमारे विपक्ष के साथी खड़े हो गये और उनको बोलने नहीं दे रहे थे। तो कभी-कभी गुस्सा और नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो उनके पक्ष के लोग हैं वो भी उन्हें बुरे लगने लगते हैं क्योंकि वो किसी और की तारीफ कर रहे हैं। खैर इस बजट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम सबने पढ़ी जो माननीय उप-राज्यपाल जी ने बोली। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकती थी। ये जो आप छोटी सी किताब देख रहे हो ये बहुत छोटी है। अगर उन कामों में रोड़ा न लगता जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, अगर इनके अक्सर डरते नहीं उस केन्द्र सरकार से, अगर एलजी साहब सच में ये मान लेते कि हां ये उन्हीं की तो सरकार है तो ये किताब इतनी भारी होती कि मुझसे ऐसे उठती नहीं। बार बार कहा गया इसमें पहली लाईन में जब शुरूआत करी कि

दिल्ली की जो औसत आय है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 2.6 परसेंट अधिक है लेकिन मेरे मन में एक विचार आया की अगर ये राशन को घर-घर पहुंचाने देते जैसे हमने पंजाब में पहुंचाया तो लोगों को राशन मिलता, बेईमानी कम होती। तो वो जो पैसे बचते उसको गरीब आदमी जाकर बाजार में लगाता। जो दवाइयां इन्होंने हमारे मोहल्ला क्लीनिक में रोकने की कोशिश करी और शायद कुछ समय के लिए ही सही उस गरीब आदमी को बाहर जाकर खरीदनी पड़ी वो पैसा बचता। फरिश्ते योजना जिसको इन्होंने रोक़ा जिसके अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसका सस्ता फ्री इलाज होता था इन्होंने रोक़ा। आप सोचिये ये जितनी भी योजनाएं इन्होंने रोक़ी अगर ये इन योजनाओं को नहीं रोकते तो उस गरीब आदमी के पास में कुछ पैसे बचते। उस पैसे का वो क्या करता अगर वो थोड़े पैसे होते तो थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करता। फिर जाकर कोई महिला अपने लिए एक साड़ी लेकर आती तो कहां पैसे खर्च होते बाजार में घूमते। और पैसे इक्ठ्ठे होते वो अपने लिए आभूषण ले आती पैसे कहां लगते फिर बाजार में घूमते। बहुत पैसे इक्ठ्ठे हो जाते तो शायद कुछ अपनी जमीन खरीदने की सोचता तो पैसे बाजार में आते। जब पैसे बाजार में आएंगे तो अर्थव्यवस्था घूमेगी लेकिन क्या करा उन्होंने उन सारे कामों को रोक़ा उस गरीब आदमी के उन पैसों को को रोक लिया। ये 2.6 परसेंट कैसे बढ़े, ये जो आमदनी है ये पूरे देश में दिल्ली की सबसे ज्यादा कैसे है क्योंकि जो पानी के ऊपर बिल आता है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 20 हजार लीटर फ्री दिया हुआ है वो पैसे

बचते हैं। इसके लिए इन्होंने अनाप-शनाप बिल बना दिये इस बार कि लोग परेशान हों लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि अंतिम सांस तक जब तक ये दिल्ली का बेटा है ऐसे गलत बिल किसी को भी भरने की जरूरत नहीं है। बिजली के बिलों में कितने साल हो गये हमने बिल बढ़ने नहीं दिये, उसका पैसा बच रहा है गरीब आदमी का। महिलाएं जो बस में जाती थीं वो पैसा बच रहा है। आखिरकार पैसे का करते क्या हैं जब लोग बचाते हैं, जैसा हमने बताया वो पैसा बाजार में ही आता है। जब बाजार में आएगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अब आईआरएस आफिसर का दिमाग है पैसा बचेगा तभी बाजार में आ सकता है। तो ये 2.6 परसेंट 5 परसेंट, 6 परसेंट या 7 परसेंट हो सकते थे अगर ये हमारे कामों को नहीं रोकते। जितने पन्ने इनके ऊपर आप खोले जाएंगे अगले पन्ने पर आप आएंगे तो उसके अंदर लिखा होगा भई खेल में हमने क्या-क्या काम करे, हमने कितने स्कूल खोले। अरे ये तो जमीन ही नहीं देते हमको। अगर ये जमीन दे देते तो कितने हम स्कूल खोल देते। जितने भी आप इनपर पन्ने खोले जाएंगे 19 स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम प्रारंभ की गई। अरे सर अगर हमको नौकरी भी किसी की लगानी है तो हमको इनके हाथ-पैर जोड़ने पड़ रहे हैं की साहब उसके लिए आवेदन निकालने दो उसको नहीं निकालने देते। अगले पन्ने पर आओगे तो 537 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 5 महिला मोहल्ला क्लीनिक, 172 एलोपैथिक औषधालय, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 30 पॉलीक्लिनिक और 38 मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क। आप इन सबमें मिनिमम गुणा दो कर लीजिए जो

हम कर सकते थे जो हमें करने नहीं दिया गया। और मुझे यह बताते हुए जो बार-बार मैं कह रहा हूँ न की खुशी हो रही है कि इतना बड़ा नेटवर्क इंडिया में कहीं नहीं है जो हमारे पास है लेकिन साथ-साथ एक दुख भी है की जो हो सकता था उसको करने नहीं दिया गया। जिस पन्ने पर आप जाओगे चाहे पढ़ाई पर जाएं, वन नेशन वन कार्ड पर जाएं, आज भी मैंने लेबर कार्ड के ऊपर आपको बात बताई की हम कितना, सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करिये राजेश जी प्लीज।

श्री राजेश गुप्ता: मेरा सर यही बात कहनी है कि जैसे मैंने बताया की आज ये जो पन्ने आपके पास में हैं ये बहुत छोटे हैं। अगर दिल्ली की सरकार को एलजी साहब काम करने दें और एलजी साहब के ऊपर केन्द्र सरकार काम करने दे मैं आपको गारंटी देता हूँ सिर्फ एक साल दे दो आप इस किताब को उठा नहीं पाओगे इतने काम हम दिल्ली में करके दिखा देंगे। तो आपके माध्यम से एलजी साहब से निवेदन है, पहले धन्यवाद है उन्होंने इन बातों को रखा लेकिन साथ-साथ एक निवेदन है कि एक साल हमारा साथ दे दो चार साल हम नहीं कह रहे एक साल दे दो एक साल करके देखिये और उसके अंदर एक अलग ही मजा आएगा। आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रीति तोमर जी।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: अध्यक्ष जी, आपने मुझे एलजी साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कुछ लाईस अपने आदरणीय सीएम सर के लिये डेडिकेट कर रही हूँ।

“चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें
 मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा
 कठोर छाती धकेल देती वापिस मुझे
 बटोर हिम्मत मैं बार बार वापिस आता रहा
 धूल धुल गयी जब सच के आईने से
 धूल धुल गयी जब सच के आईने से
 मेरी कोशिशों का रंग असर दिखाता रहा।
 टूट रहा था वो पत्थर भी धीरे धीरे
 साध निशाना मैं वार हर बार बरसाता रहा
 बिखर रहा था वो इस चोट से जर्जर जर्जर
 देख साहिल मैं उस पार रास्ता बनाता रहा
 कट गया पत्थर मेरी रूकावटों का
 धुन उमंग के गीतों की मैं गाता रहा
 चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें
 मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा।”

थैंक्यू। अध्यक्ष जी, उस दिन एलजी साहब ने मेरी सरकार कह कर संबोधित किया, अच्छा लगा। लेकिन इस बात को दिल से भी मानते तो और अच्छा लगता। इसके बाद विपक्ष के मेरे भाईयों का इस तरह से बाधा डालना वन बाई वन बहुत ही नागवार गुजरा। मुझे लगता है अध्यक्ष जी इन लोगों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। हमारी सरकार के हर काम में कभी खुद से, कभी एलजी साहब के माध्यम से बाधा डालना, क्या ये उचित है। अगर वाकई आप दिल्ली की जनता की भलाई चाहते हैं तो आपको हमारी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिये। अध्यक्ष जी, 2013 में हमारी सरकार बनी थी, 2024 चल रहा है। दिल्ली की जनता जानती है हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर नहीं, दिल्ली का बेटा बनकर काम किया है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी ध्यान रखा है। आम जनता की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुजुर्ग-विधवाओं की पेंशन, तीर्थयात्रा, महिला सुरक्षा एटसेट्रा। एक लंबी फेहरिस्त है। अध्यक्ष जी, मैं इन सभी चीजों पर वन बाई वन समय सीमा का ध्यान रखते हुए कुछ कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहूंगी।

एजुकेशन - मोस्ट इंपोर्टेंट। शिक्षा क्षेत्र के लिये बजट का कुल 21 परसेंट रखा गया है। ये इंडिया के सभी स्टेट से ज्यादा है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सुधार किया है वो किसी से छुपा नहीं है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल का डंका आज देश और दुनिया में बज रहा है। उन्होंने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को

बाहर के देशों में ट्रेनिंग के लिये भेजा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, क्वालिटी एजुकेशन दी, परिणामस्वरूप परेंट्स आज प्राईवेट स्कूल्स से निकाल कर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन दिला रहे हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं। आज अध्यक्ष जी, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 98 और 99 परसेंट आ रहा है। आज हमारे बच्चे बड़े बड़े प्रेस्टिजियस एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। 2023-24 में 15 नये सरकार स्कूल खोले गये हैं, 19 स्कूल्स में साईंस स्ट्रीम स्टार्ट की गयी है, हैपीनेस करिकुलम जैसे प्रोग्राम भी शुरू किये गये हैं, स्कूल आफ स्पेशलाईज एक्सीलेंस बनाये गये हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने कैरियर के प्रति जागरूक रह सकें। 359 डिसेबल बच्चों को उनके घर पर ही शिक्षा दी जा रही है, जहां तक स्पोर्ट्स की बात है अध्यक्ष जी, दिल्ली के 11 खिलाड़ियों ने चीन के झांगजू में लास्ट ईयर एशियन गेम्स में 11 पदक जीते। नेशनल स्कूल गेम्स में 2023-24 में भी हमारी दिल्ली 127 पदकों के साथ पहले स्थान पर रही।

हैल्थ - अध्यक्ष जी, हैल्थ की बात करें तो बजट का 12 परसेंट दिया गया है। अध्यक्ष जी, Health remains a primary focus of our government 537 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स, 5 महिला मोहल्ला क्लिनिक्स, 172 एलोपैथिक औषधालय, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 30 पॉलिक्लिनिक और 38 मल्टीस्पेशियल्टी हॉस्पिटल का नेटवर्क है। 14,244 बेड्स की क्षमता के साथ 4 करोड से अधिक रोगियों को सेवा प्रदान की गयी है। दिल्ली में अध्यक्ष जी, क्योंकि ये हर जगह से लोग आते हैं और इन सुविधाओं का लाभ लेते हैं। आज ये लोग मुख्यमंत्री

अरविंद केजरीवाल की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए जाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। मोहल्ला क्लिनक्स में ढाई सौ से अधिक टैस्ट फ्री और निशुल्क दवायें हैं जिसमें कुछ समय से केंद्र सरकार ने जो बाधा डाली है हम सबकी तरफ से हंबल रिक्वेस्ट है अध्यक्ष जी सरकार का बदला जनता से न लें।

पेंशन- अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी ने सेवा करने की इस कड़ी में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन देने का भी ध्यान रखा है। लगभग 9 लाख लाभार्थियों को दो हजार से ढाई हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। एससी, एसटी, ओबीसी कम्यूनिटीज़ के लिये 8 स्कॉलरशिप स्कीम्स भी लाई गयी हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। 715 करोड़ की लागत से रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भवन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्ष: प्रीति जी, कंकल्यूड करिये।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: अध्यक्ष जी, स्क्टी के प्वाइंट आफ व्यू से बात करें तो 1 लाख 35 हजार 500 सीसीटीवी कैमराज लगाये गये हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, चोरी डकैती, दूसरी अन्य वारदातें हैं, पानी जिसे जीवन कहते हैं लास्ट 10 साल में पीने के पानी की क्षमता में 13 परसेंट की वृद्धि हुई है। दिल्ली जलबोर्ड की क्षमता 2013 में 836 एमजीडी थी, 2023 में बढ़कर 995 एमजीडी हो गयी है।

इलेक्ट्रिसिटी की भी इंपोर्टेंस पानी से कम नहीं है। पिछले 8 वर्षों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गयी हैं और ये दरें सभी पड़ोसी राज्यों में सबसे कम हैं और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है।

(समय की घंटी)

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर: अध्यक्ष जी, इसी तरह के कुछ अनगिनत काम हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सारी बाधाओं को पार करते हुए किये हैं। दिल्ली की जनता के लिये किये हैं। अभी तो यात्रा शुरू हुई है बहुत आगे जाना है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। अच्छा लगेगा कि केंद्र सरकार भी इस स्तर में हमारा साथ दे, हम सबकी शुभकामनायें दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। बोलने का मौका दिया अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार: अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जब मैं एलजी के अभिभाषण की बुकलेट पढ़ रहा था तब मेरे मन में दो विचार आ रहे थे जिसमें एक तो दिल्ली सरकार द्वारा किये गये काम की तारीफ जो है एलजी साहब द्वारा की जा रही थी, उसके बखान किये जा रहे थे और वहीं पर जो है वो एलजी साहब द्वारा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार के स्टॉलकर दिये गये, रोक दिये गये। कुछ काम जो है दिल्ली सरकार द्वारा जिसकी एलजी साहब ने तारीफ करी जोकि अपने आप में एक बेंचमार्क है जैसे कि पीडब्ल्यूडी

द्वारा मेरे क्षेत्र में कुछ ही दो तीन सालों में पिछले तीन फ्लाईओवर जो है वो बनाये गये। आश्रम अंडरपास बनाया गया, आश्रम फ्लाईओवर, डीएनडी एक्सटेंशन बनाया गया, सराय काले खां फ्लाईओवर बनाया गया। इतने शानदार काम जो हैं दिल्ली सरकार द्वारा किये गये जो पिछले 15-20 सालों में नहीं हो पाये थे वो सारे काम जो हैं दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में करके दिखाये, यूरोपियन स्टार्इल में इतने शानदार सड़क, राजघाट में नेहरू नगर के आसपास लाजपत नगर के आसपास इतनी शानदार सड़क जो है मदन लाल जी का भी एरिया पड़ता है उसमें से कुछ, इतने शानदार सड़कें वहां पे जब लोग जाते हैं तो वहां पे सेल्फी, फोटो, वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे किसी फॉरेन में घूम रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इतनी शानदार वहां पे सड़कें बनी हैं streetscaping में। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार द्वारा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनायी गयी है उसकी कुछ दिन पहले वीडियो देखी, ऐसा लगता है कि वो किसी हावर्ड यूनिवर्सिटी की फोटो है या वहां की वीडियो है। इतनी शानदार वहां की व्यवस्था, इतनी शानदार वहां पे कल्चर और दिल्ली सरकार जिस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि नेशनल गेम्स में 127 पदक जो है वो दिल्ली के बच्चों ने जीते हैं जिसमें देश में प्रथम स्थान जो है दिल्ली के बच्चों ने हासिल किया है 127, सबसे ज्यादा पदक जो है दिल्ली के बच्चों ने जीते हैं नेशनल गेम्स में। अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटल इनकम की बात करें तो पर कैपिटल इनकम जो है वो दिल्ली की ढाई गुना अधिक है बाकी प्रदेशों से या नेशनल

पर कैपिटल इनकम जो है उससे ढाई गुना अधिक है और दिल्ली का रेवेन्यू जो है अपने आप में क्योंकि मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं तो इसलिये मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार को या किसी भी ऑर्गनाइजेशन को स्टेबल कर दो उसके रेवेन्यू जो है उसको बरकरार रखना या बढ़ाना कितना मुश्किल होता है लेकिन अपने आप में मुझे लगता है सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि दिल्ली सरकार जो है हमेशा इसका रेवेन्यू जो है वो सरप्लस में रहा है। भले ही एलजी साहब बजट सैंक्शन नहीं करते लेकिन रेवेन्यू हमारा सरप्लस में है। अधिकारी जो है वो कांटेक्टर की पेमेंट नहीं करते लेकिन रेवेन्यू जो है आम आदमी पार्टी सरकार का वो सरप्लस में है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां आसपास के पड़ोसी सरकारें जो हैं उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है, हरियाणा की हैं ये सारी सरकारें जो हैं घाटे में चलती हैं लेकिन दिल्ली सरकार जो है हमेशा रेवेन्यू जो है सरप्लस होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है अध्यक्ष महोदय दिल्ली सरकार का। इनफ्लेशन रेट की बात करें तो दिल्ली का इनफ्लेशन रेट 3.1 है जोकि देश की एवरेज इनफ्लेशन रेट से आधा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और क्योंकि ईमानदार सरकार दिल्ली में काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी की कमिटिड सरकार दिल्ली में काम कर रही है इसलिये सारे काम जो है दिल्ली में लगातार हो पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने बताया कि छोटी सी बुकलेट जो है एलजी साहब ने जो उनके अभिभाषण में पढ़ी उसमें ये छोटे से काम जो हैं मैंने बताये। हालांकि काम तो बहुत सारे

हैं लेकिन ये और भी ज्यादा बुकलेट जो है जैसे अभी राजेश भाई ने बताया कि इतनी बड़ी बुकलेट हो जाती कि जिसको उठाना जो है बहुत भारी पड़ जाता। अगर ये काम हो जाते जोकि एलजी साहब ने कौन कौन काम रोक दिये, बहुत सारी लंबी लिस्ट है लेकिन कुछ मैं आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी जो है जो दिल्ली में होनी थी वो एलजी साहब के द्वारा जो है रोक दी गयी है। पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी सरकार इतनी शानदार डोर स्टेप डिलीवरी चला रही है कि वहां से लोगों के फोन आते हैं कि पंजाब की सरकार जो है इतना शानदार काम कर रही है भगवंत मान जी के नेतृत्व में। डोर स्टेप डिलीवरी रोक दी गयी, टीचर्स को जो है ट्रेनिंग के लिये फिनलैंड जाना था आपको पता है कि कितना बड़ा आंदोलन चलाया दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने तब जाके जो है टीचर्स फिनलैंड जा पाये। जिस तरीके से गैस्ट टीचर की परमानेंसी की फाईल जो है, उनको रेगुलराईज करने की फाईल जो है दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गयी लेकिन उसको जो है एलजी साहब द्वारा स्टॉल कर दिया गया, रोक दिया गया। दिल्ली विधान सभा के खैर वो कुछ समझते नहीं हैं, दिल्ली विधान सभा के डार्क फैलो जो हैं जो बेचारे रोजी रोटी कमा रहे थे, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम जो है वो एलजी साहब द्वारा किया गया। उनके पेट पे लात मारने का काम जो है वो इनके द्वारा किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली में एडवाइजर थे, स्पेशलिस्ट थे, कंसल्टेंट थे, ऐसे जो एम्प्लॉईज थे दिल्ली में 400 एम्प्लॉईज, उन्हें एलजी साहब द्वारा हटाने का काम किया गया। कितनी

नौकरी खायेंगे एलजी साहब लोगों की। बस मार्शल सिविल डिफेंस के बस मार्शल 10 हजार से ज्यादा थे अध्यक्ष महोदय, उनके पेट पे लात मारने का 16-17 हजार बता रहे हैं, उनके पेट पे लात मारने का काम जो है वो इनके द्वारा हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, किसी के मुंह में निवाला नहीं डाल सकते तो उसकी रोटी छीनने का भी अधिकार जो है वो किसी को नहीं है अध्यक्ष महोदय। एक तरफ तो केजरीवाल सरकार लगातार जो है लोगों को नौकरी दे रही है, दूसरी तरफ ये छीनने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

(समय की घंटी)

श्री प्रवीण कुमार: आपको पता है मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में लगातार जो है वो इन्हें सेलेरी एमसीडी के चुनाव में सेलेरी रोकने का काम किया अध्यक्ष महोदय। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, काम तो बहुत सारे हैं क्योंकि समय की भी लिमिटेशन है। अब ये ऑपरेशन लोटस के तहत ये सारा काम हो रहा है। इनको लगा कि वो ये काम में लगातार रोकते जायेंगे तो दिल्ली सरकार जो है वो रुक जायेगी या दिल्ली सरकार जो है पूरी डर जायेगी। इससे काम नहीं बनातो इन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत जो है इन्होंने ईडी, सीबीआई के माध्यम से जो है वो हमारे नेताओं को अंदर डालने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले जो है मनीष सिसोदिया जी की हियरिंग में सदन को बताना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी की एक हियरिंग में मैं पहुंचा क्योंकि वहां पे जो है मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आखिर जो है कोर्ट में चल क्या रहा

है। तो मैं वहां कोर्ट में पहुंचा और वहां पे मनीष सिसोदिया की हियरिंग चल रही थी। मैंने मनीष सिसोदिया की ओर देखा तो मैं उनकी आंखों की चमक जो है वो देख के दंग रह गया, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के दंग रह गया, उनके चेहरे का तेज जो है वो देख के रंग रह गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिये काम किया है, दिल्ली के बच्चों का आशीर्वाद उनके साथ है, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, जो चमक उनके चेहरे पे बरकरार थी वही ईमानदारी की चमक उससे ज्यादा चमक उनके चेहरे पे आज भी मौजूद है अध्यक्ष महोदय। इस सदन को मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। तो आम आदमी पार्टी सरकार के जो काम हैं लगातार वो चीख चीख के वो बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। दो लाईनें मैं कह के यहां खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय

“क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं
संघर्षपथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही
वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं
लघुता न अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो
अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं
वरदान मांगूंगा नहीं
चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो
कुछ भी करो कर्तव्यपथ से किंतु भागूंगा नहीं
वरदान मांगूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं।”

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एलजी साहब के भाषण पर बोलने का अवसर दिया और मैं एलजी साहब को भी धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार काम कर रही है। हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे आंकड़े दिए कि किस तरह से दिल्ली सरकार के काम से दिल्ली की जनता को जो फायदा हो रहा है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय की 2013 में एक चमत्कार हुआ और 2013 के चमत्कार का ही परिणाम है कि आज जितनी चर्चा इस सदन में हो रही है, चाहे इन्फ्लेशन की चर्चा हो, चाहे प्रतिव्यक्ति आय की चर्चा हो। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि 2013 में दिल्ली की जनता ने एक अभूतपूर्व काम किया। मुझे लगता है थोड़ा तुलना भी कर लें, चूँकि ये चमत्कार 2014 में भी हुआ और 2014 में भी बड़ी-बड़ी मांगों के साथ सरकार आई। बड़ी-बड़ी बातें की गई थी कि बहुत हुई मंहगाई की मार, तमाम बातें हुई थी। लेकिन 2013 के जो वादे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए वो 49 दिन में दिल्ली की जनता ने जो देखा चाहे वो बिजली का वादा हो, चाहे वो पानी का वादा हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का वादा हो, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो भी सकता है क्या। फिर 2015 में एक मैसिव मंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2014 में जो केंद्र में सरकार बनी उसके जितने भी वादे थे, मुझे लगता है, चाहे वो मंहगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे

भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का हो, चाहे वो नोटबंदी से जो दुष्परिणाम लोगों के सामने हैं, चाहे वो जीएसटी से दुष्परिणाम हुए, वो जनता के सामने हैं। एक भी ऐसे वादे जो इम्प्लीमेंट हो, जनता को फायदा ऐसा नहीं हुआ। और बाद में वही तमाम लोग जो वादे किए उन्होंने कहा ये तो जुमला था। लेकिन 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और 2015 से जो शिक्षा में काम हुआ, जो स्वास्थ्य में काम हुआ, जो अंतिम आदमी तक बेनिफिट कैसे पहुंचे उसके लिए जो काम हुआ, आज हम अपने दसवें साल में प्रवेश कर रहे हैं और ये कहते हुए बाकी साथियों ने जैसा कहा कि ये गर्व की बात है कि आज दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन है, दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और ये क्यों है ये कोई बड़ा कोई इकोनोमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय की आज दिल्ली में हर एक परिवार को दिल्ली सरकार की सभी योजना से चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, पेंशन का हो, बसों में जाने का हो या अन्य योजना, उससे हर परिवार को दस से 15 हजार रुपए हर परिवार को बचता है। आज ये 10 से 15 हजार उस व्यक्ति का बचता है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है और जो सबसे ज्यादा इकोनोमिक्स में कहते हैं कि जो अच्छा कन्ज्यूमर हो वो देश के लिए असेट होता है। तो जो अच्छा कन्ज्यूमर चूंकि वो बाजार जाएगा, उसको जरूरत है कपड़ों की, उसको जरूरत है अपने बच्चों के खिलौने की, उसको जरूरत है अपने बच्चों के अच्छे किताब की। तो जब वो बाजार जाता है और उसको अगर सेविंग्स है तो वो पैसा बाजार में जाता है, जब वो पैसा बाजार में जाता है तो बाजार

मजबूत होता है, जब बाजार मजबूत होता है तो फिर सरकार को टैक्सीस ज्यादा आते हैं, जब सरकार के टैक्सीस ज्यादा आते हैं तो फिर वेलफेयर का काम ज्यादा होता है। तो ये जो इकोनोमिक्स का साइकल है इस साइकल के कारण आज दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन है और प्रतिव्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। मैं आपको दो-तीन चीजें संज्ञान में आपको लाना चाहता हूं, चूंकि आज देश के या यूं कहूं विश्व में नामचीन शिक्षामंत्री का अगर नाम आएगा तो मनीष जी का नाम आएगा, चूंकि मनीष जी ने जो शिक्षा में काम किया, वो अभूतपूर्व काम है। एक स्कूल से 45 बच्चे एनडीए का इजाम पास कर लेंगे, देश के किसी सैनिक स्कूल का रिकॉर्ड नहीं होगा, ये क्यों हो रहा है, चूंकि मनीष जी का ये पैशन था। लेकिन इसका इसका कोस्ट उसको क्या देना पड़ा, आज वो जेल में उनका आज एक साल पूरा हो गया, भ्रष्टाचार के केस में जेल गए थे वो। लेकिन एक साल में जेल जाने के बावजूद तमाम हजारों अधिकारी, तमाम तरह की जांच, दो साल से जांच चल रहा है लेकिन एक अठन्नी भी बरामद नहीं हुआ। मैं केंद्र सरकार की दो, देखिए भ्रष्टाचार किया है सब जानता है मैं दो उदाहरण आपको देता हूं मैं बस। एक उदाहरण देता हूं हालांकि कोर्ट से अभी फैसला आया लेकिन मुझे लगता है सदन के जरिए देश और दिल्ली को जानना बहुत जरूरी है, रफेल की बड़ी चर्चा हुई थी। और रफेल में ये कहा गया था कि 40 परसेंट से ज्यादा कॉस्ट पर वर्तमान सरकार ने ये खरीदा, मैं बस तीन-चार-पांच फैक्ट आपको रख दूंगा कि प्राइमाफेसाइ जो एक आम जनता को पढ़ने के बाद में भ्रष्टाचार दिखता है, वो जांच

एजेंसी को ना दिखे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के इस जनतंत्र का हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, 28 अगस्त, 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा कि हम 126 मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। मई, 2011 में आईएफ ने शोर्टलिस्ट किया पूरे वर्ल्ड में दो कम्पनी को, एक dassault को किया, एक यूरोफाइटर टाइफून को किया। 31 जनवरी, 2012 में जब बीडिंग हुई तो dassault ने सबसे कम बीड किया तो dassault को ये काम दिया गया, 2012 में फ्रांस में राष्ट्रपति बनकर आए फ्रैंको होलैंड और 13 मई, 2011 को फिर होल एचएएल और dassault के बीच में एग्रीमेंट हुआ जिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि एचएएल के 70 परसेंट और dassault को 30 परसेंट निर्माण की जिम्मेदारी होगी, ये जो एयरक्राफ्ट आएगा और उसमें कहा गया कि 108 तो निर्माण होगा जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एचएएल का होगा और 18 एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट जो है फ्लॉइवे कंडीशन में इंडिया को देगा। 16 मई, 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। एक जुलाई, 2014 को फ्रांस का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया, उसने कहा ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इसको जल्दी से कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग में थे, डिफेंस मिनिस्टर उस समय अरूण जेटली जी थे। उन्होंने कहा कि इस साल के एंड तक यानि दिसम्बर तक हम सारे टर्म कन्डीशन आपके पूरे कर देंगे और हमारा काम इसपर शुरू हो जाएगा। 8 अगस्त, 2014 को संसद में रक्षामंत्री अरूण जेटली जी ने कहा कि हमारा 18 फ्लॉइवे जो रफेल आना है वो तीन से चार साल में आ जाएगा, बाकि 108 जो

एयरक्राफ्ट है वो 7 साल, यानि 2021 तक इंडिया में आ जाएगा। 7 दिसम्बर, 2014 को जब विदेश मंत्री वहां के थे जीन एयरड्राइन वो इंडिया आए और तब रक्षा मंत्री बन गए मनोहर पारिकर साहब। मनोहर पारिकर साहब को उन्होंने कहा कि ये क्लाइमेट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको जल्दी से पूरा कीजिए। पारिकर साहब ने कहा कि एक जनवरी 2015 को कहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है जी डील में और डील में प्रॉब्लम इसलिए हो गई है कि पहले जो एग्रीमेंट था वो inexperienced लोगों ने किया था और कॉस्ट उसका बहुत कम है। अब 2015 में देखिए की Dassault ने कहा कि नहीं ये जो कहा गया है ये गलत बात है हमारा कंडीशन जारी है और 8 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, बस तीन मिनट में कन्क्लूड कर देता हूं कि फ्रांस में जब प्रधानमंत्री गए तो प्रधानमंत्री, विदेश सचिव थे जयशंकर साहब जो अभी आज के विदेश मंत्री हैं, वो विदेश सचिव थे उस टाइम। उनसे पूछा गया फ्रांस में पूछा एक रिपोर्टर ने अभी जो आ रहे हैं प्राइमिनिस्टर क्या वो रफेल की डील के लिए आ रहे हैं और रफेल की डील के लिए आ रहे हैं तो क्या उनके साथ विदेश मंत्री क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं रफेल की कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ एक बिग पिक्चर के लिए आ रहे हैं। दो दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी रफेल की डील हो गई है और इस डील में हम अब 36 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, अब उस 36 एयरक्राफ्ट में हमारा पुराना जो एग्रीमेंट था वो चलता रहेगा, चूंकि हमें

और एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो 36 हम फलाईवे एयरक्राफ्ट लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर अचरज होगा, वो जो एयरक्राफ्ट का कॉस्ट था, जो एग्रीमेंट पहले हुई थी उस एयरक्राफ्ट के एग्रीमेंट से 40 परसेंट ज्यादा कॉस्ट पर हुआ था जबकि सारा सामान उसी तरह का था जो 2011 में एग्रीमेंट हुआ था और उससे भी अचरज की बात ये है कि जब प्रधानमंत्री जी जब संसद में जानकारी दी गई कि ये कितने का एक एयरक्राफ्ट पड़ा तो उन्होंने कहा कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत 6 सौ करोड़ रुपए है, जबकि वहां पर दासॉल्ट ने जब ये कहा कि इस एयरक्राफ्ट की कीमत कितना है तो उन्होंने अपनी एनवल रिपोर्ट में 1600 करोड़ जारी किया था।

माननीय अध्यक्ष: कन्कलूड करिए संजीव जी, एक सैंकंड।

श्री संजीव झा: तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय की प्राइमाफेसाइ जो करप्शन दिख रहा था वो करप्शन इन्वेस्टीगेशन एजेंसी को नहीं दिख रहा था और उस समय जो सीबीआई चीफ थे, वो जब एफआईआर करने लगे तो रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया और जो फैसला आया, जो अभी राज्यसभा में सांसद हैं, उस समय सीजीआई हुआ करते थे, उन्होंने कहा किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। तो इस तरह से भ्रष्टाचार की जांच केंद्र सरकार कर रही है। इसी तरह से पीएम केयर फंड की बात करें तो कहते हैं कि पीएम केयर्स फंड जो है वो प्राइवेट एनटीटी है। कभी कहते हैं नहीं ये गवर्नमेंट एनटीटी है, कभी कहते हैं ये बना कैसे तो कहते हैं जब ये बना तो इसमें पीएम केयर कर रहे हैं, लेकिन पीएम केयर कर

रहे हैं, लेकिन कभी कोई डिस्मिशन नहीं हुआ और इसमें जो पैसे आए उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसको आरटीआई के दायरे में नहीं है। तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से वर्तमान में केंद्र में बैठी सरकार लूट रही है। जो प्राइमाफेसाइ एक-एक जनता को डिटेल पता चल जाए तो लगेगा की बड़ा करप्शन हो रहा है। वो देश investigating agency सीबीआई, ED को पता नहीं चल रहा है। तो मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, की एक सरकार दिल्ली में जो दिन रात दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है, जिन्होंने शिक्षा का मॉडल दिया वो जेल में है, जिन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल दिया वो जेल में। तो मुझे ये लगता है कि खुद तो काम कर पाते नहीं लेकिन जो सरकार काम कर रही थी उसको दिन-रात परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से इतना ही कह देना चाहता हूं कि एक साल मनीष जी हो गया आज जेल गए, चिंता ना करो। एक साल, डेढ़ साल, दो साल तुमको जब तक रखना है रख लो, निकलना तो एक अठन्नी का करप्शन नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस गीदड़ भभकी से, ना तो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमों है अरविंद केजरीवाल जी, ना उनके एक मंत्री, ना उनके एक विधायक डरने वाले हैं। तुम कितना भी सताना हो, तुम सता तो सकते हो किस्मत नहीं लिख सकते, ये लड़ाई बदस्तुर मजबूती से जारी रहेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद ढेर सारा आभार।

माननीय अध्यक्ष: श्री बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली सरकार निरंतर ये दावा करती है कि हमारा जो शिक्षा मॉडल है वह वर्ल्ड क्लास है। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार के बजट में ढाई गुणा बढ़ोतरी हुई है, मगर रिजल्ट 14 फीसदी तक कम हुआ है। मैं जरूर चाहूंगा कि इस पर सरकार जवाब दे। डीडीए ने दिल्ली सरकार को 13 नए स्कूलस बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। आखिर क्या कारण है कि डीडीए द्वारा दी गई जमीन पर स्कूलस क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलस में 7000 ईडब्ल्यूएस के जो कोटे की सीटें हैं वह खाली पड़ी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानकारी देना चाहता हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग है। पिछले साल उच्चशिक्षा के नाम पर सिर्फ दो छात्रों को ही लोन दिया गया और प्रचार के ऊपर 19 करोड़ 27 लाख रुपया खर्च हुआ। मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। आज दिल्ली के स्कूलस में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। ज्यादातर स्कूलस में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई हो नहीं रही है। गैस्ट टीचर्स को नियमित करने का वायदा आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से किया गया। गैस्ट टीचर्स को रैगुलराइज किया नहीं गया। स्कूलस में टीचर्स की भारी कमी है, उस कमी को दूर

किया जाए, मैं आपके माध्यम से ओनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करना चाहता हूँ जहाँ तक हैल्थ की बात है, आखिर कैसा वर्ल्ड क्लास हमारा हैल्थ सिस्टम है। अल्ट्रासाउंड के लिए 2025 की डेट मिल रही है। अगर किसी को अल्ट्रासाउंड कराना है तो 2025 की डेट मिल रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी हाईकोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि दिल्ली में लगभग तीन करोड़ लोग रहते हैं और उनके लिए केवल 6 सीटी स्कैन है। अमूमन वे भी खराब रहते हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है और आदरणीय अध्यक्ष जी मैं दिल्ली के ओनरेबल हैल्थ मिनिस्टर ने कोर्ट में क्या कहा है, वो 4 लाइनें आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि मौजूदा अस्पतालों में डॉक्टरों की कुल स्वीकृत संख्या का 33 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। डॉक्टरों के 75 प्रतिशत पद खाली हैं और पैरामेडिक्स के बीस प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। अब आप बताइये की होस्पिटलस में मैडिकल स्टाफ नहीं, नॉन मैडिकल स्टाफ नहीं। ओनरेबल हैल्थ मिनिस्टर ने इस बात को कोर्ट में स्वीकार किया है तो हम कैसे दिल्ली को वर्ल्ड क्लास जो हैल्थ सिस्टम देना चाहते हैं, कैसे वो सम्भव हो पाएगा और मोहल्ला क्लीनिकों में लैब जांच में फर्जीवाड़ा पाया गया है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जांच में 65 हजार से ज्यादा टैस्ट फर्जी पाए गए। तो आदरणीय अध्यक्ष जी मैं जरूर चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में ओल्डएज पेंशन बनानी बंद कर रखी है, बड़ी संख्या में दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों ने नई ओल्डएज पेंशन बनाने के

लिए आवेदन किया है, आखिर क्या कारण है कि ओल्डएज पेंशन बनाकर नहीं दी जा रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी मैं इस हाउस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये जरूर श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से मांग करता हूं कि राशनकार्ड बनाने बंद है। जिन लोगों ने राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है उनको राशनकार्ड बनाकर दिये जाएं। इस एलजी एड्रेस में इस बात की चर्चा की गई है कि हम दिल्ली में लगभग 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं इस हाउस में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार 72 लाख राशन कार्डधारियों को हर महीने 4 किलो गेहूं एक किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है, मैं इस सदन से चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी एलजी एड्रेस में ये चर्चा भी की गई है कि जो प्रगति मैदान के साथ टनल बनाई गई है, सुरंग बनाई गई है जिसकी लम्बाई लगभग डेढ़ किलोमीटर है लगभग उसके ऊपर एक हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार का खर्च हुआ है। ये भी कहा गया है कि उसमें 6 अंडरपास हैं, यह टनल आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा बनाई गई है और इस हाउस में मैं दिल्लीवासियों की ओर से अपनी पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आदरणीय।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: कन्कलूड करिए, हो गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): मैंने अभी शुरू किया है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं 12 मिनट हो गए, मैंने किसी को भी 5 मिनट से ज्यादा अलाउ नहीं किया, आप पढ़ते रहिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अभी मैंने शुरू किया है, 5 मिनट हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं बिधूड़ी जी 12 मिनट।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): और मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, सुनने का माद्दा रखो। अरे लीडर ऑफ अपोजिशन को सुनो। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप यहां मुझे कहे जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: 12 मिनट हो गए टाइम कट रहा है, आप बोलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आप ये कोई तरीका थोड़े ही है।

माननीय अध्यक्ष: हॉ मैं रोक रहा हूं, 12 मिनट हो गए, 2 मिनट में कन्कलूड करिए प्लीज। 12 minutes have passed.

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की ओर से वायदा किया गया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे, आखिर कहां क्लीन वाटर मिल

रहा है। रेणूका बांध, किसान बांध और लखवार व्यासी बांध से जो दिल्ली के लिए पानी लाना था सरकार पानी लाने में किल रही है। गंदा पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जल बोर्ड ने लगभग 7500 घरों से पानी के सैंपल उठाए हैं, ढ़ाई हजार सैंपल्स फेल हो गए। तो सरकार को इसपर चिंता करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही मजेदार बात इस हाउस के अंदर कही गई है कि हमने पिछले 9 सालों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जानकारी दे रहा हूं, दिल्ली में पावर पर्चेज कॉस्ट के नाम पर जून, 2023 में दिल्ली के बिलों में 10 नीसदी का इजाफ़ा हुआ। इससे पहले जूलाई 2022 में 6 फीसदी रेट बढ़े थे, अगस्त 2020 में भी power purchase cost के नाम पर रेट बढ़ाये गये और आदरणीय अध्यक्ष जी जो बिजली कम्पनियों से जो LPS के रूप में जो 18 प्रतिशत पैसा लिया गया केवल 12 परसेंट लिया गया लेना था 21 हजार 2 सौ 50 करोड़ रुपया और लिया 11 हजार 5 सौ 50 करोड़ रुपया ये 8 हजार करोड़ रुपया जो दिल्ली के लोगों का इन कम्पनियों की ओर छोड़ दिया गया है तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर उनको कार्यवाही करनी चाहिये। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे जो एल.जी. एड्रेस है उसमें तो मेरे जो प्वाइंट्स हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अब हो गया बिधुड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: उन पर मुझे बोलने दीजिये ना वो भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपने, आप सब विषयों पर।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये क्या मतलब हो गया एल.जी. एड्रेस पर।

माननीय अध्यक्ष: सब विषयों पर।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अगर एक, मैं प्वाइंट टू प्वाइंट बोल रहा हूं जो एल.जी. ने बोला है।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी जितना समय निश्चित है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं आप उस पर भी मुझे नहीं बोलने दे रहे। बहुत हैरानी की बात है आप सुनना नहीं चाहते हैं। अरे सुनने का माद्दा होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष: आप पूरा बोल चुके हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं मैं कहां बोला हूं जो एल.जी. का एड्रेस है मैं उस पर बोल रहा हूं as a Leader of Opposition और मुझे हक है उस पर बोलने का, मुझे अधिकार है, किसी भी विधानसभा में ऐसा नहीं होता है कि Leader of Opposition बोलने से रोक दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष: 15 मिनट, 15 मिनट हो गये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये कहीं नहीं होता पूरे हिन्दुस्तान में। एक उदाहरण आप मुझे दे दीजिये।

माननीय अध्यक्ष: 15 मिनट हो गये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं कहाँ हो गये बीच-बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: बिल्कुल, एक बार तो।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये कोई तरीका नहीं अध्यक्ष महोदय जी।

माननीय अध्यक्ष: एक सैकेंड के लिये बोलें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अगर एक Leader of Opposition को, अरे सुनिये भई।

माननीय अध्यक्ष: आप कितनी देर बोलना, आप।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: एक fruitful discussion होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी मेरे से बात करिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: उससे काम होगा कुछ।

माननीय अध्यक्ष: आप कितनी देर बोलना चाहते हैं?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं मुझे कम से कम 20 मिनट तो आप दीजिये ना।

माननीय अध्यक्ष: 5 मिनट बोलिये और, चलिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं कोई अगर ऐसी बात कहूं जो ऑर्थोटिक ना हो.

माननीय अध्यक्ष: चलिये, जल्दी करिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ठीक है जी, मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: टाइम देख लीजिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कोलेप्स हो गया है। हम डीटीसी के लिये एक बस नहीं खरीद पाये। अब एल.जी. एड्रेस में कहा गया था।

माननीय अध्यक्ष: भई शांति रखिये प्लीज़।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: साढ़े 16 सौ इलैक्ट्रिक बसें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिल्ली को मुफ्त दी हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूं इसके लिये हमें स्वीकार करना चाहिये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: उत्तर दीजियेगा मैं समय दूंगा।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलौत): ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: देखो ना, अब ये तरीका थोड़े ही है।

माननीय परिवहन मंत्री: येबड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है कि Leader of Opposition ऑन रिकार्ड।

माननीय अध्यक्ष: कैलाश जी, आप समय लेकर बोलियेगा।

माननीय परिवहन मंत्री: ऑन रिकार्ड वो बिल्कुल Leader of Opposition दे रहे हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं ये कोई तरीका थोड़ी है अब ये देखिये मैं कभी उनको डिस्टर्ब करता नहीं।

माननीय परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी ये इश्यू जो स्टेटमेंट दिया है ये प्रिविलेज को रेफर किया जाये।

माननीय अध्यक्ष: ये कोई तरीका नहीं है अध्यक्ष जी मेरा तो समय इसीलिये खराब हो रहा है। भई मंत्री जवाब दे दें ना।

माननीय परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी समय।

माननीय परिवहन मंत्री: ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाये। ये प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाये, ये बिल्कुल इसमें है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप नेता, प्रतिपक्ष को फांसी लगा दो।

माननीय परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, मेरा ये अनुरोध है आपसे।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप नेता, प्रतिपक्ष को फांसी लगा दो।

माननीय परिवहन मंत्री: और मेरे ख्याल से पूरा सदन।

माननीय अध्यक्ष: मैं बोल रहा हूँ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप नेता, प्रतिपक्ष को फांसी लगा दो।

माननीय अध्यक्ष: मैं बोल रहा हूँ, बैठिये आप।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मेरा गला दबा दो, मेरा मुँह।

माननीय परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी ये प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: हाँ।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी ने बसों के विषय में जो स्टेटमेंट दिया है माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर वो प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाता है, चलिये शुरू करिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से ऑरनेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि आज डीटीसी 10 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है और पिछले साल 27 सौ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है आप डीटीसी के लिये एक बस नहीं खरीद पाये और डीटीसी 10 हजार करोड़ रुपये घाटे में चल

रही है और पिछले साल 27 सौ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जरूर इसके ऊपर अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दी है और जो दिल्ली का जो हमारा एक डिपार्टमेंट है डीपीसीसी उसने कहा है कि smog tower air pollution control करने में बेअसर और साथ में ये कहा है smog towers को उनका म्यूज़ियम बना देना चाहिये। अब आपकी डीपीसीसी ये कह रही है तो इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुना की सफाई के लिये भारत सरकार ने भी साढ़े आठ हजार करोड़ रुपया दिया।

माननीय अध्यक्ष: बस ये अंतिम है बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: हां, नहीं अब ये पांच मिनट भी ये बोलने नहीं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं हो गया पांच..

....व्यवधान....

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को देखिये तीन बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ दो मिनट के अंदर। ये कभी किसी, आप क्यों इतना बुरा मान रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी आप बोलिये ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: देखिये, दिल्ली सरकार की डीपीसीसी की रिपोर्ट है कि पिछले 9 सालों में यमुना पहले से और ज्यादा गंदी हो गई है, दुगनी गंदी हो गई है सरकार इस पर ध्यान दे। हमारा जो सिवरेज सिस्टम है वो पूरी तरह से बरबाद हो गया है। 61 सौ करोड़ रुपया NGT ने दिल्ली सरकार के ऊपर फाइन लगाया है, 9 सौ करोड़ रुपया एक बार लगाया है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो रिपोर्ट है मैं एक लाइन में पढ़ रहा हूं 60 percent STPs in Delhi fail to meet quality parameters. तो इसमें सरकार को जवाब देना चाहिये और अंत में मैं आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये याद दिलाना चाहता हूं कि नगर निगम के चुनाव से पहले आपने ये वायदा किया था कि हम एक साल के अंदर जितने भी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं हम उनको हटायेंगे, कूड़े के पहाड़ हटाये नहीं गये हैं मैं जरूर चाहूंगा आपके माध्यम से कि दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, अपनी कमिट्मेंट को पूरी करें जिस दिन आप अपनी कमिट्मेंट को पूरी करेंगे मैं as a Leader of Opposition दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा लेकिन जब तक आप अपनी कमिट्मेंट को पूरा नहीं करेंगे मुझे अनेकों बार भी ये मामला उठाना पड़ेगा तो दिल्लीवासियों के हित में मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, दो-तीन विषय और रह गये लेकिन कोई बात नहीं है आपकी इच्छा अगर ऐसी है तो आप हमारे से।

माननीय अध्यक्ष: राखी बिरला जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: जी जी, तो मैं धन्यवाद, आपका धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर ऑनरेबल आम आदमी पार्टी के एमएलए से आग्रह करना चाहता हूँ यार थोड़ी मेरी उम्र का तो ख्याल रखो। अरे eSaLeader of Opposition हूँ कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है भई constitutional post पर बैठा हूँ अरे दिल्लीवासियों की बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी हो गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इतना मुझे अपमानित मत करा करो, थोड़ा सा मेरी उम्र की तरफ और मेरे ओहदे की तरफ भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिये। मैं कोई ऐसी बात करूँ जिससे आपको ये लगे कि मैं उटपटांग बात कर रहा हूँ तो आप जो सज़ा ऑनरेबल स्पीकर से दिलाना चाहे दिलवायें। आपने ऑनरेबल मिनिस्टर ने कौन सी कमेटी है?

माननीय अध्यक्ष: प्रिविलेज कमेटी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: प्रिविलेज कमेटी को आपने भेज दिया है आपको ऐसा ही लगता है कि भई रामवीर सिंह बिधूड़ी की आवाज़ इस सदन में हम नहीं सुनना चाहते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी आप मुझे आदेश करो मैं अभी Leader of Opposition के पद से विधायक के पद से त्यागपत्र देकर अपने घर चला जाऊँगा।

माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: लेकिन मैंने कभी, मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही है जो मर्यादा के खिलाफ हो, लेकिन कम से कम Leader of Opposition को अपनी बात रखने दें और उसके बाद Hon"ble Chief Minister, concerned minister reply कर सकते हैं तो थोड़ा सा ज़रा आप।

माननीय अध्यक्ष: पूरे 20 मिनट हो गये हैं, बैठिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं थोड़ा समझाईये ना।

माननीय अध्यक्ष: समझा दिया मैंने, मैं बहुत समझाता हूँ, बहुत बोलता हूँ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अगर मैंने ये कह दिया साढ़े सौलह सौ बस, अरे भई उसमें केन्द्र सरकार का साढ़े छः सौ करोड़ रुपये का योगदान है।

श्रीमती राखी बिरला: बैठ जाईये, बिधूड़ी जी हो गया, हो गया हो गया बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये आपका जवाब है आपका जवाब है।

श्रीमती राखी बिरला: हो गया हो गया बिधूड़ी जी, बैठ जाईये।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी अब बैठ जाईये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आपका जवाब है, मैं इनको करैक्ट कर रहा हूँ।

श्रीमती राखी बिरला: बैठ जाईये, बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये आपका जवाब है दिल्ली सरकार का मेरे पास।

श्रीमती राखी बिरला: कृपया बैठ जाईये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती राखी बिरला: बहुत-बहुत धन्यवाद आप बैठे। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी।

माननीय अध्यक्ष: राखी बिरला जी, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में।

श्रीमती राखी बिरला: आपने मुझे, तीन मिनट लूंगी, एक सैकेंड भी ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे एल. जी. साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया और अध्यक्ष जी सच में मैं दिल की गहराइयों से एल.जी. साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आज अध्यक्ष जी जो पूरे देश में माहौल चल रहा है ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने खतरों के खिलाड़ी की तरह अपनी भूमिका निभाई। 15 फरवरी को जब वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में सरकार के द्वारा भेजे गये अभिभाषण को पेश करने आये उससे महज़ तीन दिन पहले इस देश के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना

घटी और सिर्फ तीन दिन पहले नहीं लगातार देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, ऐसे में एल.जी. साहब ने बहुत बहादूरी दिखाते हुये दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के कामों की प्रशंसा की, सराहना की मैं उसका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। एक ओर डर के माहौल में, तानाशाही के माहौल में संवैधानिक पद पर बैठे हुये लोग जहां सरकार द्वारा तैयार किये गये अभिभाषण को सदन के भीतर पढ़ने से मना कर रहे हैं। तमिलनाडू की 12 फरवरी की घटना है सदन के भीतर वहां के गर्वनर ने यह कहकर अभिभाषण को पढ़ने से मना कर दिया कि मैं सरकार के इस अभिभाषण से सहमत नहीं हूं, दूसरी ओर डर और तानाशाही के माहौल में पंजाब के गर्वनर सरकार की नीतियों से असहमति ना जतायें तो वो अपने पद के साथ अन्याय कर रहे हैं और तानाशाही के माहौल में अगर वो अपने पद पर बैठकर तो शायद उनकी जो अन्तरआत्मा है उसने उसकी गवाही नहीं दी और ऐसे माहौल में उन्होंने निजी कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे मैं दिल्ली के उपराज्यपाल का ये खतरों के खिलाड़ी वाला स्टंट और यहां आकर केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करना, अपना अभिभाषण देना लाख रूकावटों के बाद चाहे सदन के भीतर रूकावट हुई हो बीजेपी के विधायकों के द्वारा या फिर सदन के बाहर रूकावटें हुई हों उन अधिकारियों के द्वारा जो डर के माहौल में और भय के माहौल में हमारी पॉलिसिज़ को रोक रहे हैं, उन सबको तोड़ते हुये एल.जी. महोदय ने कम से कम इस सदन की और संविधान की गरिमा रखी और

उन्होंने यहां आकर केजरीवाल सरकार की नीतियों का, उनके कामों का जो बखान किया, मैं सच्चे दिल की गहराईयों से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने संविधान की और इस सदन की और इस सरकार की मर्यादा रखी। लेकिन सर से जानना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय कि जो व्यक्ति सदन के बाहर एक चुनी हुई सरकार की हर नीति का विरोध करता है, चुनी हुई सरकार की फाइलों को दबाने का काम करता है, वो यहां आकर क्यों अपने तानाशाही जो उनके आका हैं उनको जाकर उसे रिपोर्ट करना है, उस डर को भी अलग दूर करते हुये, उस डर को भी किनारे रखते हुये क्यों वो यहां पर आकर उस जो अभिभाषण को पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि केजरीवाल सरकार की जो नियति है और जो नियत है, जो उनकी पॉलिसिज़ हैं वो जनहित से जुड़ी हुई है और जहां जनहित की बात आती है, आप चाहे कितने ही ष्टाड़यंत्र कर लें, आप चाहे कितनी ही तानाशाही कर लें, आप मजबूर हो जाते हैं एक इन्सान होने के नाते आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सरकार उसके हितों के लिये काम कर रही है उसका बखान आपको करना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम कर रही है चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तीर्थ यात्रा हो, यातायात हो हर एक वो काम जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुये व्यक्ति के हित को साध सकता है, उसे आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकता है, उसको सामाजिक तौर पर सम्मान दिला सकता है, उसको शिक्षाविद् बना सकता है, हर एक काम को करने का जो प्रयास लाख

अवरोध उत्पन्न करने के बावजूद, तमाम विरोध करने के बावजूद, अधिकारियों का बिल्कुल हाशिये पर फाइलों को डालने के बावजूद जो ऐतिहासिक काम मेरी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किये, मैं इसके लिये पूरी सरकार को, पूरे सदन को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि संविधान की जो हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है लेकिन आपकी नीतियों से प्रभावित होकर लाख रूकावटें डालने वाले लोग भी यहां पर आकर आपके भाषण के माध्यम से सरकार की तारीफ करते हैं, उनकी नीतियों की तारीफ करते हैं, सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, जय हिन्द जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आज मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूंगा। आज ही के दिन एग्जैक्टली एक साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था, मेरे बगल में बैठा करते थे यहां पर और बिल्कुल झूठा केस है लेकिन हम इस वक्त उनका दुःख नहीं मनायेंगे, हमें उन पर गर्व है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने देश के लिये बहुत बड़ा काम किया है गरीबों के बच्चों को भविष्य देने का, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का, सपने देखने का, उनके सपनों को पूरा देने का उन्होंने काम किया है। 75 साल में जो सारी सरकारें कोई सरकार नहीं कर पाई वो काम उन्होंने किया है। तो ज़ाहिर तौर पर

इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब-जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी इस सदन से सबसे मैम्बर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं, आप भी हो जाओ, अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया, थैंक्यू।

आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं एल.जी. साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं पक्ष के विपक्ष के लेकिन सदन जनतंत्र का मंदिर माना जाता है, इसकी मर्यादा बनाये रखना जरूरी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन इस बार और पिछली बार ऐसा हुआ कि एल. जी. के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने काफी नारेबाजी और विघ्न डाला, सुनना तो चाहिये सुन तो लो, सुनकर आपको भी अब मौका मिला आपने बोला अपनी बात रखी उस टाइम अभिभाषण में अगर विघ्न डालते हैं तो वो फिर राजनीति नज़र आती है वो अच्छी बात नहीं है वो मर्यादा तोड़ने की बात हो जाती है। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथी जो हैं विपक्ष के वो भविष्य के अंदर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। एल.जी. साहब ने दिल्ली सरकार के कामों का उल्लेख किया, दिल्ली सरकार आज जो काम कर रही है वो ऐतिहासिक काम है। 75 साल में जो ये सारी सरकारें, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी हम तो नई पार्टी हैं, हमसे पहले सारी पार्टियों की सरकारें बनी, किसी की इस राज्य में बनी किसी की उस राज्य में बनी, किसी की यहां बनी किसी

की वहां बनी, किसी की केन्द्र में बनी। जो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहा है वो 75 साल के अंदर नहीं हुआ और अगर 75 साल में हो गया होता तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कोई शौक नहीं था राजनीति के अंदर आने का। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है, किसी कोने में चले जाओ गांव-गांव के अंदर किसी कोने में चले जाओ, अभी थोड़े दिन पहले कोई आया था बहुत बड़ा नेता वो बता रहा था बिहार के गांव-गांव में आप चले जाओ वहां भी कहते हैं यार स्कूल तो हमें दिल्ली वाले चाहिये, स्कूल तो हमें दिल्ली जैसे चाहिये। पूरे देश के अंदर आज चर्चा हो रही है। तो आज दिल्ली मॉडल में बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं, पानी में भी काफी काम करना बाकी है। दिल्ली में बिजली ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिये, अस्पताल ठीक कर दिये, मोहल्ला क्लीनिक बना दिये, सड़कें ठीक कर रहे हैं, सीवर ठीक कर रहे हैं बहुत सारे काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। ऐसे काम हो रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रखने के लिये बहुत जरूरी हैं जोकि 1950-1960 में हो जाने चाहिये थे। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जानी चाहिये थी, हर व्यक्ति के लिये अच्छे इलाज का इंतजाम हो जाना चाहिये था, वो काम आज हो रहा है। आज दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल आज पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है और ये मैं केवल कहने के लिये नहीं कह रहा मैं तीन सेक्टर्स का जिक्र करूंगा, एजुकेशन, हैल्थ और इलैक्ट्रिसिटी। कई सारे जिक्र किये जा सकते हैं, ये तीन सेक्टर्स का मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से इन तीन सेक्टर्स में

दिल्ली में जो काम हुये हैं उससे पूरे देश का कैसे उद्धार हो सकता है, पूरे देश का उस मॉडल से कैसे विकास हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, पहले मनीष सिसोदिया जी को हम याद कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पूरे देश में ये कहने की बात नहीं है तर्क-कुतर्क तो चलते ही रहते हैं अभी जो आप बात कर रहे थे वो तो कुतर्क है मतलब किसी भी क्लासरूम के अंदर घुसकर एक कैमरा लेकर अरे-अरे देखो ये मिट्टी देखो-देखो-देखो लेकिन मोटे-मोटे तौर पर आज सारे मानते हैं भई अच्छा काम हो गया शिक्षा के अंदर, शिक्षा में अच्छा काम हुआ है। जिस तरह से जितना इन्वेस्टमेंट हमने शिक्षा में किया है सरकारी स्कूल बहुत सारे अच्छे बन गये, बहुत शानदार सरकारी स्कूल बन गये। सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है कि चार से पांच लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर सरकारी स्कूल में भर्ती हुये हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को बड़े-बड़े, बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल-निकालकर सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना ऐसा था जब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे, सरकारी स्कूल में चला जाये तो साल दो साल में नाम कटा देते थे कि टाइम खराब कर रहा है, घर बैठेगा दो पैसे तो कमायेगा। आज अगर हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी तो पूरे देश में भी दे सकते हैं, पूरे देश में आज क्या मॉडल चल रहा है। गुजराज के अंदर पिछले कुछ सालों में 6 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिये गये। असम के अंदर कोविड के बाद साढ़े चार हजार सरकारी स्कूल बंद कर

दिये गये। ऐसा नहीं कि वहां पर पोपुलेशन कम हो गई, पोपुलेशन तो बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं, गरीब भी बढ़ रहे हैं पोपुलेशन भी बढ़ रही है और स्कूल खोलने की जरूरत थी और स्कूल खोलने की बजाय अगर 6 हजार स्कूल इधर बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है हर राज्य के अंदर यही चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद किये जा रहे हैं, क्यों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सरकारी स्कूल बंद कर करके, सरकारी स्कूल बंद कर करके आपके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट में दाखिला ले लो। दिल्ली छोड़कर, एक तरह से शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरा देश चल रहा है। जबरदस्ती की जा रही है, गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, ना टीचर हैं वहां पर ना पढ़ाई है वहां पर। साढ़े तीन सौ स्कूल बताते हैं वहां पर ऐसे हैं जिसमें एक क्लास रूम है गुजरात के अंदर। एक क्लास रूम है। एक क्लास रूम में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं सारे बच्चे एक ही क्लास रूम है। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में अच्छे क्लास रूम हैं, अच्छे डैस्क हैं, स्मार्ट क्लास रूम हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो आज ऐसी हालत है एक तरह से पूरा देश के अंदर मॉडल अब ये है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ धकेला जा रहा है। बच्चों को फोर्स किया जा रहा है। गरीबों को फोर्स किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल अब बंद करेंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो। ऐसे में दिल्ली एक उदाहरण है, दिल्ली एक मॉडल दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कैल्कुलेशन करी है। हमने

दिल्ली में जितने शानदार स्कूल बनाये देश में दस लाख सरकारी स्कूल हैं जिनमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। पांच लाख करोड़ रुपये के अंदर देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाये जा सकते हैं। मात्र पांच लाख करोड़ के अंदर। पांच लाख करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के लिए कुछ नहीं होते। दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल मान लो एक-एक लाख करोड़ रुपये भी हर साल खर्च करोगे तो पांच साल के अंदर एक-एक लाख करोड़ और आधा अगर आप कह दो भई राज्य सरकार देगी, आधा हम देंगे तो ढाई लाख करोड़ रुपये ही लगेंगे केन्द्र सरकार को। पांच लाख, मात्र पांच लाख करोड़ रुपये के अंदर में हम इस देश के हर बच्चे को 17 करोड़ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उनको अच्छा भविष्य दे सकते हैं और पांच साल में अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, इस देश से गरीबी दूर हो जायेगी। गरीबी को दूर करने का, इस देश से गरीबी खत्म करने का मैं एक रामबाण तरीका दे रहा हूं। भाषण देने तो बहुत आसान है। गरीबी हटाओ, फलाना इस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिये, उस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिये, गरीबी दूर करने की इच्छा किसी की नहीं है। आज मैं आपको इस सदन के माध्यम से पूरे देश को एक मॉडल दे रहा हूं कि जो स्कूल हमने, सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाये इतने अच्छे शानदार प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे बड़े-बड़े नामी गरामी प्राइवेटों स्कूलों से भी अच्छे, स्वीमिंग पूल वाले, लिफ्टों वाले और स्मार्ट बोर्ड वाले क्लास रूम जो हमने बनाये मात्र पांच लाख करोड़ रुपये के अंदर गांव-गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाये जा सकते हैं। दूसरी चीज पर आते हैं, हैल्थ पर।

आज दिल्ली के हर व्यक्ति को हम लोगों ने मुफ्त इलाज कर दिया कि आपका इलाज मुफ्त होगा। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिये। जगह-जगह मोहल्ला क्लीनिक खोल दिये। मुझे यह बात कहते हुए बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले दो साल के अंदर। पिछले दो साल में जिस तरह से एलजी साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाईयां बंद कर दी, टैस्ट बंद दिये। लड़-लड़कर मैंने उसको दोबारा चालू कराया। लड़-लड़कर दोबारा। ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया। हैल्थ जिसने ठीक करी, उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया। फिर भी जब अस्पताल चल रहे थे तो उनकी डॉक्टरों की भर्ती, जो खिड़की के ऊपर आदमी बैठता है, वो.. डेटा इन्ट्री ऑपरेटर एक दिन ऑर्डर पास करके सारी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डेटा इन्ट्री ऑपरेटर हटा दिये। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन खिड़की पर कोई नहीं बैठा था, दवाईयों की खिड़की पर कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन की खिड़की पर कोई नहीं, ये क्या है और फिर इस सदन के अंदर आकर इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़ें हैं। अरे तुमने करें हैं सरकारी अस्पताल खराब। आज सरकारी अस्पताल हमने इतने शानदार, लड़-लड़कर उसको व्यवस्था को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुरूस्त रहें। सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिये। ये लोग बार-बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल

है, स्कैंडल है। सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है। आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भई तेरे को एक कार्ड देंगे, इन्श्योरेंस कार्ड। वो कार्ड लेकर आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ आपके परिवार का साल में पांच लाख रुपये का इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी कब जब उसका होस्पिटलाइजेशन होगा। उसको खांसी है, बुखार है, रोजमर्रा की दवाईयां वो नहीं मिलेंगी, दवाईयां नहीं मिलेंगी, टैस्ट नहीं होयेंगे, डेली के डेली का अगर बाई-चांस कोई बड़ी बीमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा, तो परिवार का साल का पांच लाख रुपये का खर्चा मुफ्त है, इन्श्योरेंस। अब वो इन्श्योरेंस लेकर क्या करें? उत्तराखंड में चले जाओ आप कहीं अस्पताल नहीं है। पचास-पचास, कोस-कोस दूर लोग अपनी खटिया के ऊपर वो डंडी सिस्टम क्या कहते हैं उसको.. 'पालकी' हों वो लेकर जाते हैं वो वहां पर एक लोकल टर्म है, वो अस्पताल तो बनायेंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेकर वो क्या करें? कार्ड लेकर कहां जायें इलाज कराने के लिए? अरे अस्पताल तो बनाओ पहले। अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाईजेशन के दौर की तरफ है। सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं। एक कार्ड पकड़ दिया कि प्राइवेट में जाकर अस्पताल में इलाज करा लो। आयुष्मान भारत, दूसरा उसमें ये लिखा हुआ है कि केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय सालाना ढाई लाख रुपये से कम है। ढाई लाख रुपये मतलब बीस हजार रुपये। बीस हजार के लगभग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है। बीस हजार, जिसके तीस हजार रुपये हो गए वो

इलाज करा सकता है? आज इतना महंगा इलाज हो रहा है वो इलाज करा सकता है? तीस हजार रुपये, चालीस हजार क्या पचास हजार रुपये वाला भी अगर एक हार्ट अटैक हो जाये इलाज नहीं करा सकता अपना। कह रहे हैं आयुष्मान भारत, उस पर पांच लाख की लिमिट। दिल्ली के अंदर का जो मॉडल है। मैं पहले 'आयुष्मान भारत' बता दूँ। उसमें ये भी लिखा है, सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पर। दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है। सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में compulsory है। हमारे पीछे पड़े हैं इसको लागू करो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको। हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाये कि प्राइवेट में जाये। जहां जायेगा उसको पांच लाख रुपये तक का सरकारी में भी पांच लाख तक का फ्री मिलेगा, प्राइवेट में भी। अरे हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर। हम पांच लाख की लिमिट क्यों लगाये, हम पांच लाख की लिमिट क्यों लगाये? आप कहते हो कि सरकारी अस्पताल में, पहली बात तो हम पैसे लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे तो पैसे लेंगे। दवाई लेंगे तो पैसे लेंगे। डॉक्टर जो पैसे हैं उसकी वो उसकी जो consultancy charge चार्ज लेंगे और वो पांच लाख रुपये तक। हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया। सारों का फ्री कर दिया। ये कहते हैं ढाई लाख रुपये की इन्कम वालों को देंगे। हमने तो सारे अमीर, गरीब सबका फ्री कर दिया। तो तुम्हारी आयुष्मान भारत अच्छी है, हमारा केजरीवाल मॉडल अच्छा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इनकी आयुष्मान भारत अच्छी

है, जीटीबी अस्पताल में अभी चले जाओ बार्डर पर है दिल्ली और गाजियाबाद के बार्डर पर, जीटीबी अस्पताल में 80 परसेंट पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू हैं पिछले चार से, फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुडगांव के तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ। उधर नरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए और वो प्राइवेट में नहीं आ रहे सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी में पांच लाख की लिमिट नहीं है जितना मर्जी इलाज करा लो। अरे पूरे देश का बोझ उठा रखा है आज दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने। ये बता रहे हैं नजफगढ़ के अंदर, सारे हरियाणा के लोग नजफगढ़ के अंदर हरियाणा वाले। अरे आयुष्मान भारत लागू है वो इधर क्यों आ रहे हैं फिर इलाज कराने के लिए और इतना भ्रष्टाचार है अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी ने आयुष्मान भारत का सितम्बर 2018 से 2021 तक उन्होंने जांच करी। 964 अस्पतालों की जांच करी, 161 जिले 28 स्टेट्स एंड Union Territories उसमें उन्होंने पाया दो लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका डेट ऑफ डिस्चार्ज डेट ऑफ सर्जरी के पहले था। मतलब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया सर्जरी बाद में हुई है। अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया सर्जरी बाद में हुई है, तो नेक केस थे ये। 46 हजार केस ऐसे निकले जिसमें डिस्चार्ज की डेट एडमिशन की डेट से पहले थी। मतलब आदमी डिस्चार्ज पहले हो गया एडमिशन बाद में हुआ। दो लाख से ज्यादा केस ऐसे निकले जो मरे

हुए लोगों के थे। ढेरों केस ऐसे निकले जो अडल्ट्स के थे और उनको pediatrician ने इलाज कर रखा था। बच्चों के डॉक्टर से इलाज करा रखा था अडल्ट्स ने। नौ लाख केस ऐसे निकले जिसमें एक ही फोन नम्बर था 9999999999 ये फोन नम्बर नौ लाख लोगों का निकला। इस तरह के बहुत घपले निकले। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुष्मान भारत कह रही है। ये इनका मॉडल है और हमारा मॉडल है हमने शानदार अस्पताल बनाये। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। हमने शानदार अस्पताल बनाये। हमने ये भी जो अभी आप माननीय ओपोजिशन लीडर ने अभी बोला कि अल्ट्रासाउंड की या किसी की 2025 की डेट मिल रही है। हम 'फरिश्ते' स्कीम लेकर आये हैं। हम एक और डाक स्कीम लेकर आये हैं जिसमें अंदर ये है कि अगर आप को किसी भी टैस्ट की एक महीने से बाद की, एक महीने से ज्यादा डेट मिलती है तो प्राइवेट से इलाज करा लो उसका खर्चा हम देंगे। आपके एलजी साहब ने इस स्कीम को भी रोक दिया। आपके एलजी साहब ने इस स्कीम की भी पेमेंट नहीं होने दी। जाकर रोओ एलजी निवास में, राज निवास के अंदर जाकर रोओ कि वो क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को दुखी कर रखा है उन्होंने और आप ही लोग करा रहे हो। ये गंदी राजनीति कर रहे हो, ऐसे मत करो। ये ठीक बात नहीं है। पाप चढ़ेगा आप लोगों को। ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले से डरो। अब हमारा मॉडल है। अब हमारा मॉडल है गली-गली के अंदर मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे। गली-गली के अंदर सबको दवाईयां फ्री देंगे। किसी को छोटी-मोटी बीमारी है उसको दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मॉडल

है, हम बड़े-बड़े शानदार अस्पताल बनायेंगे, किसी को फोर्टिस, मैक्स, अपोलो क्यों जाना पड़े। हम ऐसे अस्पताल बनायेंगे हमारे वाले ही फोर्टिस जैसे लगेंगे, हमारे वाले ही मैक्स जैसे लगेंगे, दिल्ली सरकार के अस्पताल। हमने इतने शानदार अस्पताल बना दिये। पूरे देश के अंदर शानदार अस्पताल और गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लीनिक खोलने के लिए मात्र पांच लाख करोड़ रुपये का खर्चा है। मैंने सारा कैल्कुलेट कर लिया। मैंने तो दिल्ली में खोलकर दिखाये हैं अस्पताल। मैंने तो दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक खोलकर दिखाये हैं। पंजाब में खोल रहे हैं अब। पंजाब के अंदर अभी मैं जा रहा हूं आठ सौ मोहल्ला क्लीनिक बना दिये। साढ़े छः सौ बन चुके हैं और मैं दो दिन बाद जा रहा हूं सवा सौ मोहल्ला क्लीनिक का उद्घाटन और करने के लिए। तो मोहल्ला क्लीनिक खोलने आते हैं। अस्पताल पंजाब के जितने है सिविल हॉस्पिटल हैं चालीस अस्पतालों का अभी जीर्णोद्धार चल रहा है। हर अस्पताल के अंदर मुफ्त दवाईयां, मुफ्त टेस्ट सब कुछ मुफ्त कर रहे हैं। मुफ्त इलाज देना। पांच लाख करोड़ रुपये के अंदर इस देश के 140 करोड़ लोगों को फ्री इलाज मिल सकता है। हमें देना आता है। तो आज देश को स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर भी दिल्ली ने एक दिशा दिखाई है, कर सकते हैं। अब आते हैं बिजली पर। दिल्ली के अंदर पहले बिजली के पावर कट लगते थे। आज चौबीस घंटे बिजली आती है। गर्व होता है देश की राजधानी है। पंजाब के अंदर पहले पावर कट लगते थे। डेढ़ साल हुआ है, दो साल हुआ है सरकार बने हुए। दो साल के अंदर चौबीस घंटे बिजली आती है। हमारे देश में क्यों नहीं आती चौबीस घंटे बिजली?

दस साल हो गए आपकी सरकार बने हुए। देश के अंदर इतने पावर कट क्यूं लगते हैं, किसानों को पूरी बिजली क्यूं नहीं मिलती, इण्डस्ट्री को पूरी बिजली क्यूं नहीं मिलती, हमारे घरों के अंदर गांव-गांव के अंदर बिजली क्यूं नहीं मिलती? आपको ये जानकर अब जो डेटा मैं दे रहा हूं, आपको जानकर ताजुब होगा। देश के अंदर बिजली की कमी नहीं है। देश में चार लाख मेगावाट बिजली की installed capacity है। हम चार लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं और हमारे देश की डिमांड कितनी है। पीक डिमांड जो गर्मियों के अंदर पीक डिमांड आती है ना जब एकदम उबल रही होती है, धरती उबल रही होती है, पीक डिमांड जून जुलाई की जो हमारे देश की डिमांड है वो है दो लाख मेगावाट। हमारी जरूरत दो लाख एविलेबल चार लाख, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं। इतनी निकम्मी सरकार तो आज तक कभी नहीं देखी... हमसे सीख लो। हम मना थोड़े ही कर रहे हैं। हम सिखाने को तैयार हैं। हम यहां राजनीति करने नहीं आये। हम यहां राजनीति करने नहीं आये। हम यहां पर आपको सिखा देंगे। आप लो वो सारे वोट, मैं तो उस दिन भी कह रहा था, सारे वोट तुम्हारे जिम्मे। देश की सेवा करने की जिम्मेदारी हम को दे दो। हम सेवा करके दिखा देंगे। वोट सारे आप ले लो। चार लाख मेगावाट की installed capacity है। दो लाख मेगावाट की हमारी डिमांड है। हमें बिजली क्यूं नहीं मिल रही, जवाब दे सरकार। कई लोग कहते हैं हम ने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, ये sustainable model नहीं है। मैंने ये भी कैल्कुलेट करा। पूरे देश के हर आदमी को दो सौ युनिट बिजली

फ्री देने के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये चाहिए बस। केवल डेढ़ लाख करोड़ रुपये में पूरे देश को सारे हर परिवार को दो सौ युनिट बिजली फ्री मिल सकती है। तो पांच लाख करोड़ रुपये में स्कूल ठीक हो जायेंगे। पांच लाख करोड़ में अस्पताल ठीक हो जायेंगे तो डेढ़ लाख करोड़ रुपये में सबको बिजली फ्री हो जायेगी। साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपये के अंदर आपके बच्चों को 140 करोड़ लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जायेगी। उनके हर परिवार के सदस्य को अच्छा इलाज मिल जायेगा। चौबीस घंटे बिजली मिल जायेगी। हर व्यक्ति को फ्री बिजली मिल जायेगी और ग्यारह लाख करोड़ रुपये इन्होंने अपने दोस्तों को उठाकर उनका ऋण माफ कर दिया। क्या ज्यादा जरूरी था? क्या ज्यादा जरूरी था, दोस्ती निभाना ज्यादा जरूरी था कि 140 करोड़ लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी था? अभी और भी बहुत सारे सैक्टर्स हैं। आज पंजाब के अंदर हमारी सरकार, भगवंत मान सरकार जो खेती के क्षेत्र में कर रही है। गांव-गांव, घर-घर के अंदर उन्होंने खेती का पानी पहुंचा दिया। अभी तक पानी नहीं आता था। लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। हमने किसी से भीख नहीं मांगी और पानी की। उसी पानी का मैनेजमेंट करके गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर खेती का पानी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा, ऐसी सरकार हो सकती है। दो साल के अंदर हर खेत के अंदर खेती का पानी पहुंच गया। खेती के क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। आज पंजाब के अंदर एक बड़ा चमत्कार हुआ है। केन्द्र की बीजेपी सरकार ने एयर पोर्ट बेच दिये, सीपोर्ट बेच दिये, एलआईसी बेच दी, भेल बेच दी, रेल बेच दी। सब

कुछ बेच दिया और कह रहे हैं एक-एक बेचने में स्कैंडल है, स्कैंडल है। हर चीज जो बेची इन्होंने सब कुछ बेच दिया। पंजाब के अंदर गंगा उल्टी बह रही है। एक पावर प्लांट था, प्राईवेट सैक्टर में। छः हजार करोड़ रुपये का प्राईवेट वालों का पावर प्लांट था उनसे चल नहीं रहा था, सरकार ने उसको ग्यारह सौ करोड़ रुपये में.. हम चलाकर दिखायेंगे, हम चलाकर दिखायेंगे। तो आज पूरे देश को एक तरह से आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है वो एक दिशा दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। दुख बस है तो इस बात का है कि हमारे कामों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने तो कभी किसी से दुश्मनी की नहीं है। हम तो हाथ जोड़कर चलते हैं। हमें क्या लेना देना। राजनीति करनी हमें आती नहीं है। तो हमारा ये ही है हमें भी काम करने दो, आप भी काम करो। आपको हम सिखायेंगे। आप सारे वोट आप लो। हम से काम सीखो। आप करो काम। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पार्टी भी हम से सीख ले, वो वाली पार्टी भी हम से सीख ले हमें कोई। तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: अब श्री गोपाल राय माननीय..

माननीय मुख्यमंत्री: मेरी सबसे निवेदन है, मनीष जी को एक साल हुआ है तो इसके बाद सदन अभी खत्म हो जायेगा, पांच दस मिनट में हम सब लोग मिलकर राजघाट पर चलेंगे और वहां पर गांधी जी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके आयेंगे।

माननीय अध्यक्ष: अब श्री गोपाल राय माननीय विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने है। ये सदन उप-राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2024 को विधान सभा में दिये गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है।

ये प्रस्ताव सदन के सामने है
जो इसके पक्ष में हैं वे हों कहें,
जो इसके विरोध में है ना कहें।
(सभी सदस्यों के हों कहने पर)
हों पक्ष जीता, हों पक्ष जीता,
प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय उप-राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना भिजवा दी जायेगी।

अब सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था है। भोजन करके राजघाट पहुंचेंगे।

(सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।
